आकस्मिक घटना होती है कि इसकी पूर्व सूचना, खासतौर से ठीक स्थान, किस समय और कितने समय के लिए घटेगी, यह बताना संभव नहीं है, ह्युमनली पोसिब्ल नहीं है। ऐसा कहीं नहीं हुआ अभी तक। यहां रेडियो, टी० वी०, नहीं है वहां कैसे गई सूचना, तो यह सिर्फ एक संभावित क्षेत्र के विषय में कहा जा सकता है, पर वह इतने कम क्षेत्र को प्रभावित करता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र प्रभावित होगा, इतनी देर तक होगा, इतना नुकसान होगा। महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की आपने चर्चा की और महाराष्ट्र को दी गई राशि के विषय में पूछा, इस प्रकार की मांग बहुत से राज्यों से आ रही है, पर चूंकि आपने महाराष्ट्र के विषय में पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ने बाढ़, भारी वर्षा, ओलावृष्टि और सूखा के कारण हुई क्षति के संबंध में मांग भेजी थी और उनको 53.98 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस पूरे वर्ष की मैं कह रहा हूं।...(व्यवधान)...महाराष्ट्र सरकार को कुल 53.98 करोड़ की, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इतनी राशि दी जा चुकी है पूरे वर्ष में और यह मांग कई प्रदेशों से आ रही है और जो पैस्ट अटैक की एक नई परिभाषा इसमें जोड़ दी गई है, इससे इसकी विषयावली का भी बहुत विस्तार होगा कि किस तरह इसको पूरा किया जाए। कई बार राजनीतिक कारणों से और बिना पूरी तरह विचार-विमर्श के इस तरह की बात करने से हानि होने की बात है। हम इस सारे को रिव्यू करेंगे समीक्षा करेंगे और मैं सदन को बताऊंगा। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सदस्यों का।

SHRI W. ANGOU SINGH (Manipur): Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has not given clarification to my question regarding the exclusion of Manipur from the list of States.

SHRI SOM PAL: Mr. Angou Singh, I have also not been able to find the name of Manipur. I will try to find out why it is not there and I will inform you. I undertake to inform the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. Shri Balwant Singh Ramoowalia.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—CONTD.

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा नम्बर, 4, 12, 15, 22, 28 और 36 पर मायूस

[उपसभाध्यक्ष (जी त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) पीठासीन हुए]

होकर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। पैरा 28 में कहा गया है...(व्यवधान)...

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहब, मैं यहां अकेला मिनिस्टर हूं, मैं चेयरमैन साहब से बात करने के लिए जा सकता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वसीम साहब, सिकन्दर बख्त साहब थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं?

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): बिल्कुल। हम इस वक्त कोई इन्कार नहीं करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (जी त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वसीम साहब की इजाज़त में पूरे सदन की इजाज़त है।

श्री बलवन्त सिंह रामुवालिया: तो मैं पैरा 28 में ...(व्यवधान)...

श्री वसीम अहमद: मैं आप ही की बात कह रहा हूं। उपसभाध्यक्ष जी, अब आप हाउस में देखिए कि पूरे हाउस में चार मैम्बर और मुश्किल से 10-12 लोग हैं, पूरा मीडिया खाली हो गया है। अब अगर सिर्फ हमको रिपोर्टिंग करानी है तो हम करा देंगे। जब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है तो बिना वजह ये खानापूर्ति हो रहा है। मेरी समझ में इससे कोई फायदा नहीं होगा हाउस को।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जो सदस्य बोलना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, यहां आए हैं, उनको कम्प्लीट करा दें।

श्री वसीम अहमद: कल करा लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, कल संभव नहीं होगा।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to make a suggestion. Those hon. members who are present here intend to speak. You indicate those who are present here and

allow them to speak tomorrow. You cannot allow all the members to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): It has already been decided in the meeting of the Business Advisory committee that the Prime Miniter...*(Interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, these statements were not there when the Business Advisory Committee met. They have taken four hours. *(Interruptions)*...

श्री वसीम अहमद: सर, चार घंटे लग गए स्टेटमेंट में। स्टेट्मेंट्स में चार घंटे लग गए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): No. *(Interruptions)*... I am sorry. One person at a time. *(Interruptions)*...
One person at a time.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, these two statements have taken away four hours from the time allotted for the discussion on the Motion of Thanks on the Pesident's Address. So, that much time should be given. You cannot expect members to sit up to 12 o'Clock in the night.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI):Leaders of different parties were present at the time of BAC meeting and this was agreed and the Chairman made it clear that there was no proposal to extend the session futher. One of the leaders said that some Members would be leaving the House before 7o'clock or so and that the session must end by tommorrow 5 o'clock and so on. We had also ascertained the convenience of the Prime Minister. He was supposed to give his reply today. but he was gracious enough to accede to our request and he said that he would not mind and he would make himself available tomorrow morning. Under these circumstances and when the Chairman has already taken a decision in the business Advisory Committee meeting and in the presence of all party leaders, my submission is that we should continue the business schedule as it is.

सदन के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहब, आपकी इज़ाज़त से मैं ऑनरेबल मैंबर्स को यह बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैंबर्स को एकॉमोडेट करने के लिए हाऊस को एक दिन नहीं, बल्कि दो दिन बढ़ाया गया। बहुत सारे अहम मसायल थे जिनको बीच में लाना था, इसलिए तय हुआ कि आज जितनी भी बहस होनी है, वह आज पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री जी को आज बोलना था लेकिन तय किया गया कि वे दूसरे दिन बोलें। दूसरा दिन यानी कल का दिन भी ओवरलोडेड है और किसी और चीज का उसमें इज़ाफा नहीं हो सकता। बिजनैस ऐडवाईज़री कमेटी में, चेयरमैन साहब की मौजूदगी में यह फैसला हुआ और सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए उस फैसले पर हमें स्टिक करना चाहिए और उसे बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

†[उर्दू सकंदर बख्त "तर्जुमा": सदर साहब आपकी इजाजत से मैं आनरेबल मेंबरस को यह बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेंबरस को एकोमोडेट करने के लिए हाउस को एक दिन नहीं बल्कि दो दिन बढ़ाया गया। बहुत सारे अहम मसायल थे जिनको बीच में लाना था, इसलिए तय हुआ कि आज जितनी भी बहस होनी है, वह आज पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री जी को आज बोलना था लेकिन तय किया गया कि वे दूसरे दिन बोलें। दूसरा दिन यानी कल का दिन भी ओवरलोडेड है और किसी और चीज का उसमें इज़ाफा नहीं हो सकता। बिजनैस ऐडवाईज़री कमेटी में, चेयरमैन साहब की मौजूदगी में यह फैसला हुआ और सभी पार्टियों के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए उस फैसले पर हमें स्टिक करना चाहिए और उसे बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।]

†[Transliteration in Arabic Script

لوگ اس میں شامل تھے اسلئے اس فیصلے پر ہمیں اعتراض کرنا چاہیئے اور اسے بحث کا مدعا نہیں بنانا چاہیئے۔]

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): यह बहस का मुद्दा नहीं है, एतराज का मुद्दा है। ऐतराज़ का मुद्दा इसलिए है कि आप सबसे ज्यादा नज़्म ज़ब्त की बात के क़ायल हैं और आप हमें ज़ाब्ते सिखलाते भी हैं। ज़ाब्ता यह नहीं है कि जो डिस्कशन अभी हुआ वह होता। पहले बहस हो जाती राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर और आखिर में जब सब बोल लेते, उसके बाद ये बहस होनी चाहिए थी, जो पहले हो गई और 4 घंटे उसमें लग गए।

श्री सिकन्दर बख्त: आपको शायद मालूम नहीं है कि हमेशा यह कायदा है कि जब किसी मिनिस्टर का स्टेटमेंट करना होता है तो कार्यवाही को रोककर स्टेटमेंट दिया जाता है। इसमें कोई नयी बात नहीं है।

†[श्री सिकन्दर बख्त: आपको शायद मालूम नहीं है कि हमेशा यह कायदा है कि जब किसी मिनिस्टर का स्टेटमेंट करना होता है तो कार्यवाही को रोककर स्टेटमेंट दिया जाता है। इसमें कोई नयी बात नहीं है।]

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मैं भी आपके नोटिस में यह बात ला दूं कि चेयरमैन साहब ने ऐहतियात के तौर पर सदन से यह पूछा था कि क्या मंत्री महोदय का स्टेटमेंट पहले ले लिया जाए सोमपाल जी का स्टेटमेंट तो बिजनैस में छपा हुआ था। मैं समझता हूं कि इस पर और समय खराब न करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस जारी रखनी चाहिए। रामूवालिया जी, आप बोलिए।

श्री बलवन्त सिंह रामुवालिया (उत्तर प्रदेश): पहले आप पक्का कर लीजिए क्योंकि जब मैं खड़ा होता हूं तभी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): पक्का हो गया। सब बात चंगी हो गई यहां पर।

श्री बलवन्त सिंह रामुवालिया: महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 4, 12, 15, 22, 28, 36 पैराग्राफ्स पर नाखुशी और असंतुष्टि का इज़हार करते हुए मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं। महोदय, अभिभाषण के पैराग्राफ 28 में यह लिखा है कि—

"The Government is committed to initiate action to carve out Uttarakhand, Vananchal and Chattisgarh".

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि नए प्रदेश बनाने से बहुत से और मसले उभरेंगे। आप पंजाब को ले लीजिए। पंजाब का प्रदेश बना लेकिन अभी तक चंडीगढ़ नहीं मिला और न ही अभी तक पंजाबी भाषा-भाषी क्षेत्र पंजाब को मिले हैं और पंजाबी भाषा को पड़ोसी राज्यों में लागू करने का संत लोगोंवाल से जो वायदा था, उस पर भी अमल नहीं हुआ है। अभी पंजाब के दरियाओं के पानी का झगड़ा है, भाखड़ा-नंगल भी किसको देना है, वह झगड़ा भी है। ये झगड़े रहेंगे। इसलिए इस पर दोबारा गौर किया जाए।

महोदय, उत्तरांचल बनाते वक्त आपको देखना होगा कि पीलीभीत और उसके साथ डा० अम्बेडकर का जो डिस्ट्रिक्ट है और बाजपुर और नानकमत्ता, ये जो इलाके हैं, यहां पंजाबी और बंगाली बहुत रहते है। ये लोग उत्तरांचल में नहीं जाना चाहते। इसलिए ऐजीटेशन होगा, गड़बड़ होगी, यह मैं आपको आगाह कर देता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर उत्तरांचल बनता है तो इन इलाकों को उत्तरांचल से बाहर रखना चाहिए और इन लोगों की राय ली जानी चाहिए कि ये शामिल होना चाहते है या नहीं।

महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दलित, पिछड़े, वर्ग, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड-ट्राईब्ज तथा माईनोरिटीज़, इनका जिक्र अभिभाषण में बहुत कैजुअल तरीके से किया गया है। इन लोगों के जो मुद्दे हैं, इनका जिक्र आपने ऐसे छेड़ा है जैसे इनके कोई मुद्दे ही नहीं हैं। जैसे हम एक्सट्रा वगैरह लिख देते है। तो उनके बेसिक मुद्दे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अल्पसंख्यकों की बात करते वक्त मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन को 125 करोड़ करने का वायदा करेंगे? क्या अल्पसंख्यों की विधिक संस्थाओं को मान्यता देने का जो प्रश्न हमेशा रहता है उसको आप मानेंगे? क्या जो पंजाबियों की ओर सिखों की दिल्ली पुलिस में भर्ती पर अन-डिक्लेयड्र बेन है उसकी बात करेंगे? क्या आप ऐसे उपाय करेंगे जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की पदोन्नति को रोकने वाले अफसरों को सजा दी जाए? क्या मॉयनोरिटी डवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन का जो बजट है, जो उसका शेयर केपिटल है उसको बढ़ाने के लिए इजाजत

†[ ]Transliteration in Arabic Script

देंगे? इसमें यह कुछ भी नहीं कहा गया है इसलिए मुझे मायूसी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के बारे में आपने एक अच्छी बात कही है। आपने लिखा है कि बच्चों का चरित्र और बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सारे दिन टी०वी० पर, सरकारी टेलीविजन पर सुपरस्टिशन जादू-टोना, ताबीज और भूत-प्रेत दिखाकर आप बच्चों को भविष्य में साईंस से, विज्ञान से जोड़ रहे हैं या विज्ञान से तोड़ रहे है? जो तर्कशील सोसाइटी बनी है सारे देश में उनकी बात को रेडियों और टेलीविजन पर लाना चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नम्बर-22 पर खेतीबाड़ी की बात कही गई है। बिल्कुल छोटे किसान, गांव में रहने वाले खेतिहर मजदूर और छोटे किसानों के बच्चों की तालीम छोटे किसानों के बच्चों की नौकरी, उसकी बेटी की शादी और दान-दहेज में जो खर्चा होता है वह तो इन मुसीबतों में घिर गया है। उसको कोई दवाई नहीं, छोटे किसान को अपनी फसल की इतनी अच्छी आमदनी नहीं और इस पर भी उसको महंगा तेल लेना पड़ता है। उस तेल में मिलावट होती है। डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट की जाती है। पंजाब में पिछले एक वर्ष में एक भी पैट्रोल पम्प पर छापा डालकर यह पता नहीं किया कि क्या डीजल से मिट्टी का तेल मिलाकर इंजन बरबाद हो रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं कि आप खेतीबाड़ी की पैदावार बढ़ा सकेंगे? थीन डैम तो उसी तरह पड़ा हुआ है। कहीं तो पानी पाकिस्तान को जा रहा है और यहां पानी नहीं है पंजाब में। पंजाब में पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है। उसको रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं। अगर नहीं करेंगे तो सिंकल इरिगेशन हो सकती है, ड्रिप इरिगेशन हो सकती है। पंजाब देश को 70 फीसदी अनाज देता है। अगर ऐसे प्रदेश में पानी जमीन के नीचे चला गया और जमीन बंजर बन गई तो कहां-कहां से अनाज मंगाएंगे? यह मुसीबत आने वाली है। मैं एक बात और जोर से कहना चाहता हूं। श्री सिकन्दर बख्त जी....**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब आपका समय भी हो गया है, मेहरबानी करके।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: वाईस चेयरमेन साहब, मैं आपके जरिए कहता हूं कि आज तक भाजपा के खिलाफ यह इल्जाम कभी नहीं लगा कि वह राष्ट्र को तोड़ना चाहती है। लेकिन आपको शायद पता नहीं कि एक इतना गलत काम हो चुका है तथा आप पर यह इल्जाम भी लगने वाला है कि भाजपा के हाथों देश की एकता और अखंडता को खतरा है। वह इल्जाम क्या है? वह इल्जाम नहीं, वह सूरज की तरह सच्चाई है। सच्चाई यह है कि भाजपा की राजस्थान सरकार ने पंजाबियों को और विशेषकर सिखों को राजस्थान में खेती की जमीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता हूं। मैं तो मसले का हल चाहता हूं। राजस्थान में सिख जमीन नहीं खरीद सकते, पंजाबी जमीन नहीं खरीद सकते। क्योंकि रामूवाला गांव, मोंगा खन्ना की बात छोड़ो। श्री कृष्ण कांत जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं।

गुजराल जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, चीफ जस्टिस पुन्छी और एयर चीफ मार्शल सरीन राजस्थान में ज़मीन खरीदना चाहें और कहें कि हम पंजाब के रहने वाले हैं तो इन्हें ज़मीन नहीं मिलेगी। अगर*

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपने अपना प्वाइंट मेक्अप कर लिया?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: एक मिनट.....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) :आगे बढ़िए। कोई और प्वाइंट कहिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: *....**(व्यवधान)**.....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) :वैसे परम्परा यह है कि चेयरपर्सन, वाईस प्रेज़ीडेंट के बारे में या उनका नाम इन चीजों में नहीं लाया जाता। ....**(व्यवधान)**.....

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मैं कहता हूं कि उनको भी ज़मीन नहीं मिलेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : उदाहरण के लिए नहीं, मेरी समझ में any reference in this regard to the Chairman may be deleted from the records.

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मैं यह कहना चाहता हुं कि आखिर राजस्थान में पंजाबियों के ज़मीन खरीदने पर रोक क्यों लगाई है? क्या ये दो देश हैं? हम बराबर के शहरी नहीं है?.....**(व्यवधान)**.....

सदन के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): रामूवालिया जी.....मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

†[ ]Transliteration in Arabic Script

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मैं एक मिनट में पढ़ दूं?

श्री सिकन्दर बख्त :मैं तो खत्म ही कर रहा हूं, आप पढ़ दीजिएगा। सदर साहब, मेरी गुज़ारिश है आपके ज़रिए कि बात यह निकली थी कि पंजाबी ज़मीन नहीं खरीद सकते। शुरू में आपने फरमाया था कि सिख नहीं खरीद सकते हैं। उसको पंजाबियत तक ही रखिए नहीं तो उसमें एक कड़वाहट का रंग आ जाएगा ....(**व्यवधान**).....

†[شری سکندر بخت : میں تو ختم ہی کر رہا ہوں آپ پڑھ دیجئے گا۔ صدر صاحب میری یہ گزارش ہے آپ کے ذریعہ کہ بات یہ نکلی تھی کہ پنجابی زمین نہیں خرید سکتے۔ شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ سکھ نہیں خرید سکتے۔ اس کو پنجابیت تک ہی رکھئے نہیں تو اس میں کڑواہٹ کا رنگ آجائیگا۔]†

PROF. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome and support the Motion of Thanks to the President for his Address to the Joint Session of Parliament on 25th March, 1998.

Sir, paragraph 4 of the President's Address amply indicates the very spirit of the Government's intention where it is said that the parliamentary arithmetic alone cannot provide the key to good governance. the key lies in the willingness to rise above the notion of parliamentary majority and minority and work in a true spirit of co-operation, conciliation and consensus. Hence, the Government is imbued with that spirit.

Sir, I am reminded of a very interesting point about the first democracy in Greece some 2500 years ago. In this context of majority and minority it is stated:

> "A democracy is a system of unlimited majority rule, the classic example is ancient Athens. And the symbol of it, is the fate of Socrates, who was put to death legally because the majority did not like what he was saying, although he had initiated no force, and had violated no one's rights."

Sir, I, therefore, appeal to all hon. Members of this august House to follow the spirit of cooperation and consensus in order to solve the burning problems of the country which confront us. In para 10 of the Address it has been mentioned that one of the weaknesses of socio-economic policies so far has been the less than adequate attention to social sector and the Government is pledged to investing large resources in social infrastructure. Besides this, through you, Sir, attention of the House is drawn to para 18 wherein it has been stated by the Government that it will employ urgent measures to step up investment in the infrastructure sector, including power, roads, bridges, etc. I am interested especially in the power sector. I hope the Government will supplement the electricity supply by identifying and exploiting the non-conventional energy sources, specially the solar energy which perhaps is missing. Fortunately, Sir, most parts of the southern India lie in the tropical zone where the sun rays fall direct. But, it is unfortunate that in south India the peak shortage has been 18 per cent whereas in other parts it has been only 11.5 per cent. Sir, it is very suitable if we harness the solar energy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please try to be brief.

PROF. NAUNIHAL SINGH: Sir, knowing it full well that power is capital-intensive and for that matter we have to invite foreign investment which is not so easy to acquire, hence, in the *swadeshi* spirit we have to encourage promotion of more and more non-conventional sources of energy especially with the help of the abundant solar energy. Another point which, I wish to highlight is the distribution of energy. Sir, out of the total

†[ ]Transliteration in Arabic Script

energy that is generated in the country hardly 30 percent of it goes to the rural areas where 80 percent people reside and about 70 percent goes to the urban areas. This is an imbalance in the economy. This is an injustice of the highest order against the rural people and which affects the agriculture and the agriculture-based industries. Therefore, I recommend that there should be a National Rural Energy Commission which should monitor the equitable distribution of energy resources so produced.Otherwise, surely, it would be a kind of breach of fundamental rights of the citizens who can claim under the Constitution equitable distribution of national resources. Sir, I stop here although I had to say a lot. But my main emphasis is on the non-conventional energy sources. They have perhaps been neglected. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Hon. Members, I would like to inform you once again that a dinner has also been arranged for you in Room No. 70.

THE TARA CHARAN MAJUMDAR (ASSAM): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to take part in the debate on the President's Address made before the Parliament on 25th March. Several references which have been made in the President's Address are laudable. Through this Address people have been promised the moon. But in view of the financial constraints and all-pervasive corruption, it is doubtful if even 50 per cent of the assurances can be successfully executed. In respect of the assurance given in the Address for achieving success in spheres of national life, I cannot refrain from pointing out some glaring omissions in the report regarding my State and the entire North-Eastern region. This region is under turmoil for more than two decades and in the name of containing insurgency, continued presence of security forces in the region has become a permanent feature.

Sir, there is no mention in the President's Address that the question raised by the so-called insurgents are political questions requiring a political solution. Deployment of security forces for a long time for solving the problems, leads to alienation of the people from the mainstream and also lead to bad relations between the people and the security forces. The Address does not mention anything to assure the people of the region that their ethnic, cultural and social identities would be protected and that steps would be taken to control the movement of people from outside the region to maintain the demographic balance in the region. There is no mention in the Address that urgent and time-bound programmes will be initiated in the region for its development and for removal of disparities in all spheres or for removal of a sense of frustration, neglect and deprivation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please be brief.

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Sir, I will not take much time. There is no mention in the President's Address about the absence of infrastructure in the region leading to its backwardness. There is no mention in the Address assuring that measures will be taken for improvement of rail, road and air communications, that attempts would be made to generate power by harnessing the vast water resources available in the region. It is also not mentioned that proper steps will be taken for stopping the devastations caused due to repeated floods and erosion and the river Brahmaputra will be controlled and used for generation of power and other things for the betterment of the economy of the region. The economy of the State can be used for many other purposes such as water-ways. The water resources should be harnessed for the generation of power. The Address fails to mention the burning question of infiltration of foreigners from across the border. There is nothing in the

Address regarding measures to be taken for detection and deportation of foreigners from across the border. Sir, it is admitted by sources that this region is a backward region, it is underdeveloped and it requires special economic programmes. There is noting in the Address that a special time-bound programme will be taken up for removal of backwardness of the region. With these words I conclude. Thank you.

श्री मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश): मोहतरम, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने सदर-ए-जम्हूरिया साहब का खुतवा पढ़ा भी और सुना भी। मुझको बहुत उम्मीद लगी थी कि इस देश में जो 70 से 80 फीसदी तक किसान है, डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट, उनकी पैदावार की मुनाफाबख्श कीमत नहीं मिल रही है उसके सिलसिले में कोई कदम उठाया जायेगा।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां कैश क्रोप गन्ना है। किसानों का दो-दो-तीन-तीन साल का पैसा बाकी है और उनको गन्ने की कीमत नहीं मिलती है। चौधरी चरण सिंह मरहूम ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक देश के खेत और खलिहानों की हालत ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं होगा और फिर किसान बगावत पर इतना आमादा हो जाएगा जैसा कि अखबार ने कहा है कि जिस खेत से देहकां को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर उस गुन्दुम को जला दो, वहां तक पहुंच जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि खुतबे से जो उम्मीद बनी थी इस किस्म की कोई बात रहेगी। लेकिन निहायत मायूसी हुई। मोहतरम मैं बहुत ताज्जुब में हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दो साल पहले एक मैनिफैस्टो, जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी तब बनाया था। लेकिन बाद में उन्होंने दूसरा एजेन्डा बना दिया। मुझे ताज्जुब होता है कि उन्होंने दूसरा एजेन्डा बनाया। उसको बनाने की क्या जरूरत थी। जो मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति थी वही उनके मैनिफैस्टो में होनी चाहिए थी। हिन्दू-हिन्दू करके एक फिजा मुल्क की खराब कर दी। हिन्दू हम हिन्दुस्तान हमारा। हमारे वास्ते मशल-ए-राह है कि हिन्दी हम वतन है, हिन्दुस्तान हमारा। इससे आगे जाने की क्या जरूरत थी। हम बनता है हिन्दू और मुसलमान दोनों को मिलाकर, हिन्दू और माइनोरिटी को मिलाकर। लेकिन हम को तोड़ने की क्या जरूरत थी? आज हमारे नौजवान इस कदम जहर आलूद उसका दिमाग है। हमको उसकी तरफ देखना है कि अगर वह जहर आलूद दिमाग ठीक नहीं हुआ तो आज हमें प्यार भरी बात करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा और प्यार भरी बात जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जाती है तो थोड़ा सा शुबहा होता है कि आखिर उन्होंने लिखकर के दिया था राष्ट्रीय इंटीग्रेशन कमेटी और सुप्रीम कोर्ट में लेकिन उसके खिलाफ अमल से इनको बताना है, अपने-अपने किरदार से बताना है। बाकी जो प्यार की बातें कर रहे हैं, चाहे मुसलमानों के साथ चाहे दूसरों के साथ उस पर वे खरे उतरेंगे या नहीं या फिर उसी तरह से रहेंगे जैसे 1992 में हुआ है?

मोहतरम, जो लोग आज महसूस कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपनी बात दो शेरों के साथ कहना चाहूंगा।

कि कुछ कह तो गया बर के गजब ने जिसे मारा।

बिजली गिरेगी तो चाहे आह बाह, आह राम,
आह भगवान, आह अल्लाह।
कुछ तो कह जाएगा, उफ कर न सका जिसको
तेरे प्यार ने मारा।
कहीं ये नौबत न पहुंच जाए।

इस वास्ते मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मैनिफेस्टों उसी ऐतबार से बदल दीजिये जिसे आपने राष्ट्रीय एजेन्डा बनाया है। उसी के ऐतबार से मैनिफैस्टो बदल दीजिए तब जाकर आपनी बात पर एतमाद होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऊपर लागू होती है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ थी, कांग्रेस से हम नाराज थे। सब मिलकर 1977 में इलैक्शन जीतकर आए। हमने 85 में से 85 सीटें जीत लीं और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। आज हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, उनका दिमाग पता नहीं कहां फिर गया कि वे एक होकर इलैक्शन में आते तो उनका आज यह रोना न होता। भारतीय जनता पार्टी 100 से कम सीटें पाती और यह तो हम लोगों का अहसान है हमको दुवाएं दो कि तुम्हें कातिल बना दिया। वरना अगर हम सही तौर से सोचते तो आज यह नौबत न आती।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं चौधरी चरण सिंह जी का शागिर्द हूं। उन्होंने हमें यह सिखाया था कि अपोजिशन में रहकर वह बात न कहो जो सत्ता में पूरी न कर सको। हमको आज वह बात नहीं कहनी चाहिये कि वाकई रूलिंग पार्टी में आएं तो वह बात पूरी न कर सकें। हम सब लोगों ने एक मंजर देखा कि कांग्रेस के एक कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। वे 13-14 दिन तक यह

860/RS F-8B

कहते रहे कि पहले मेरी बात सुन लो फिर मुझे मुल्जिम बनाना। इसी बात को लेकर यहां हाउस को चलने नहीं दिया गया। खासतौर से जो लोग आज सत्ता में हैं, आज कौन सी ऐसी बात हो गई है कि आज वे हमको प्यारे हो गये हैं। हमने एक मंजर और भी देखा था कि एक साहब मुख्य मंत्री के खिलाफ नारा लगाते रहे कि उनको बर्खास्त करो, बर्खास्त करो।

इस इलेक्शन में वह उनके साथ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इस चीज पर निगाह होनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफार्म की शक्ल पर या किसी और शक्ल पर, अगर हम किसी मैनुफेस्टो पर इलेक्शन लड़ते हैं और अगर खुद उस मैनुफेस्टो से हट जांए तो उसे वह जगह खाली कर देनी चाहिए।

मोहतरमा, आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त कानून और व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, हर जगह खराब है। इसके लिए इस गवर्नमेंट को मैं दोष नहीं देता। यह देखा जा रहा है कि इस किस्म के दिमाग डेवलप हो रहे हैं जिससे उनमें बर्दास्त की ताकत नहीं रह गई है। सदर साहब, इस लिए छोटी छोटी रियासतें बनाई जाए। में इस राय का हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए खाली उत्तराखंड नहीं, पश्चिम, पूर्व और मिडिल इस तरह की तीन स्टेट बनाई जाए। इतना बड़ा प्रदेश होने के कारण वहां का मुख्य मंत्री तमाम जिलों के बारे में मालूम नहीं कर सकता है।

आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। यह देश की बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है, हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि :

जो उसूले गुलिस्तां से वाकिफ नहीं,
अब निजामे चमन उनके हाथ आ गया।

†[श्री मोहम्मद मसूद खां "अतर प्रदेश":
محترم - بہت بہت شکریہ - میں نے صدر جمہوریت صاحب کا خطبہ پڑھا بھی سنا بھی مجھکو بہت امید لگی تھی کہ اس دیش میں جو ۷۰ سے ۸۰ فیصدی تک کسان ہیں - ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ - ان کی پیداوار کی مناسب بخش قیمت نہیں مل رہی ہے اسکے سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا جائیگا -
مانیور میں "اتر پردیش" سے آتا ہوں - وہاں کیش کروپ گنا ہے - کسانوں کا دو دو تین تین سال کا پیسہ باقی ہے اور انکو گنے کی قیمت نہیں ملتی ہے چودھری چرن سنگھ نے کہا تھا کہ دیش کی خوشحالی کا راستہ کھیتوں اور کھلیانوں سے ہو کر گزرتا ہے - جب تک دیش کے کھیت اور کھلیانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک ہمارا دیش خوشحال نہیں ہوگا اور پھر کسان بغاوت پر اتنا آمادہ ہو جائیگا جیسا کہ اخبار نے کہا ہے جس کھیت سے دھقان کو میسر نہ ہو روٹی - اس کھیت کے ہر اس گندم کو جلا دو - وہاں تک پہنچ جائیگا - میری آپ سے گزارش ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطبہ سے جو امید بندھی تھی اس قسم کی کونسی بات رہیگی - لیکن نہایت ہی مایوسی ہوئی - محترم میں بہت تعجب میں ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے دو سال پہلے ایک مینی فیسٹو - جب انکی تیرہ دن کی سرکار بنی تھی تب بنایا تھا - لیکن بعد میں انھوں نے دوسرا ایجنڈا بنا دیا - مجھے تعجب ہوتا ہے

†] Transliteration in Arabic Script

پھر اسی طرح سے برسیں گے جیسے 1992 میں ہوا ہے۔

محترم۔ جو لوگ آج محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے لئے میں اپنی بات دو شعروں کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ۔ کچھ کہہ تو گیا ہر کے غضب نے جیسے مارا۔ بجلی گرے گی تو چاہے آہ و اہ آہ بھگوان آہ اللہ۔ کچھ تو کہہ جائیگا۔ اف کر نہ سکا جسکو تیرے پیار نے مارا۔

کہیں یہ نوبت نہ پہنچ جائے۔ اس واسطے میں یہ کہنا چاہوں گا۔ کہ آج مینی فیسٹو اسی اعتبار سے بدل دیجئے جیسے آپنے راشٹریہ ایجنڈا بنایا ہے۔ اسی کے اعتبار سے مینی فیسٹو بدل دیجئے تب جاکر آپ کی بات پر اعتماد ہوگا۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت جن سنگھ تھی۔ کانگریس سے ہم ناراض تھے۔ سب ملکر 77 میں الیکشن جیت کر آئے۔ ہم نے 85 میں سے 85 سیٹیں جیت لیں اور کانگریس ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی۔ آج ہم لوگ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف تھے۔ ان کا دماغ پتہ نہیں کہاں پھر گیا۔ کہ وہ ایک ہو کر الیکشن میں آئے تو انکا آج یہ رونا نہ ہوتا بھارتیہ جنتا پارٹی انھوں نے دوسرا ایجنڈا بنا دیا۔ اسکو بنانے کی ضرورت تھی۔ جو مینیمم پروگرام پر سہمتی تھی وہی اسکے مینی فیسٹو میں ہونی چاہیئے تھی۔ ھندو ھندوستان کے ایک ششما ملک کی خراب کر دی۔ ھندو ہم ھندوستان ہمارا۔ ہمارے واسطے مشکل یہ ہے کہ ھندی ہم وطن ہے ھندوستان ہمارا۔ اس سے آگے جانے کی ضرورت تھی ہم بنتا ہے ھندو اور مسلمان دونوں کو ملا کر۔ ھندو اور مائناریٹی کو ملا کر۔ لیکن ہم کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی آج ہمارے نوجوان اس قدر زھر آلود اسکا دماغ ہے۔ ہم کو اسکی طرف دیکھنا ہے کہ اگر وہ زھر آلود دماغ ٹھیک نہیں ہوا تو آج ہمیں پیار بھری بات کرنے سے کچھ نہیں ملیگا اور پیار بھری بات جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے کہی جاتی ہے تو تھوڑا شبہہ ہوتا ہے کہ آخر انھوں نے لکھکر کے دیا تھا راشٹریہ انٹیگریشن کمیٹی اور سپریم کورٹ میں لیکن اسکے خلاف عمل سے انکو بتانا ہے۔ اپنے کردار سے بتانا ہے۔ باقی جو پیار کی باتیں کر رہے ہیں۔ چاہے مسلمانوں کے ساتھ چاہے دوسروں کے ساتھ اس پر یہ کھرے اتریں گے یا نہیں یا

چاہیئے الیکٹورل ریفارم کی شکل پر یا کسی اور شکل پر اگر ہم کسی مینو فیسٹو پر الیکشن لڑتے ہیں اور اگر خود اس مبنی فیسٹو سے ہٹ جائیں تو اسے وہ جگہ خالی کر دینی چاہیئے۔

محترمہ - آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت قانون اور یوستھا کی حالت بہت خراب ہے - ہر جگہ خراب ہے - اس کیلئے میں اس گورنمنٹ کو دوش نہیں دیتا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس قسم کے دماغ ڈویلپ ہو رہے ہیں جس سے انہیں برداشت کی طاقت نہیں رہ گئی ہے - صدر صاحب اسلئے چھوٹی چھوٹی ریاستیں جائیں - میں اس رائے کا ہوں کہ اتر پردیش جیسے بڑے پردیش کے قانون و یوستھا کو ٹھیک کرنے کیلئے خالی اترا کھنڈ نہیں - پشچمی - پوربی اور میڈل اس طرح کی تین اسٹیٹ بنائی جائیں - اتنا بڑا اتر پردیش ہونے کا کارن وہاں کا مکھیہ منتری تمام ضلعوں کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا ہے۔

آخر میں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں - یہ دیش کی بدقسمتی ہے - ہماری بدقسمتی ہے - ہمارے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ:

... اسے کم سیٹیں ملتی اور یہ تو ہم لوگوں کا احسان ہے ہم کو دعائیں دو کہ تمہیں قاتل بنا دیا - ورنہ اگر ہم صحیح طور سے سوچتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی -

تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں چودھری چرن سنگھ جی کا شاگرد ہوں - انھوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ اپوزیشن میں رہ کر وہ بات نہ کہو جو سبھا میں پوری نہ ہو - ہم کو آج وہ بات نہیں کہنی چاہیئے کہ واقعی رولنگ پارٹی جائیں تو وہ بات پوری نہ کر سکیں - ہم سب لوگوں نے ایک منظر دیکھا کہ کانگریس کے ایک کمیونی کیشن منسٹر تھے - وہ ۱۳-۱۲ دن تک یہ کہتے رہے کہ پہلے میری بات سنو پھر مجھے ملزم بنانا اسی بات کو لیکر یہاں ھاؤس کو چلنے نہیں دیا گیا خاص طور سے جو لوگ آج سبھا میں ہیں - آج کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ آج وہ ہم کو پیارے ہو گئے ہیں - ہم نے ایک منظر اور بھی دیکھا تھا کہ ایک صاحب مکھیہ منتری کے خلاف نعرہ لگاتے رہے کہ انکو برخواست کرو - برخواست کرو - اس الیکشن میں وہ انکے ساتھ ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس چیز پر نگاہ ہونی

جو اصول گلستاں سے واقف نہیں
اب نظام چمن اسکے ہاتھ آ گیا۔

श्री वसीम अहमदः चेयरमैन सर, जो अमेंडमेंट हम लोगों ने और मैंने दिए हैं जाहिर है कि ये प्रसीडेंट एड्रेस के ऊपर हम लोगों ने दिए हैं। यह कैबिनेट की तरफ से एक फार्मुलेट की हुई चीज होती है जिसको प्रेसीडेंट पढ़ता है। इसमें प्रेसीडेंट खुद अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। यह गवर्नमेंट की पालिसी होती है और उस पर ऐतराजात हम लोग करते हैं। जहां तक प्रेसीडेंट का सवाल रहा इस पर न कोई ऐतराज करता है और न किसी को करना चाहिए। हम लोगों की हमेशा यह कोशिश रहती है कि जो गवर्नमेंट कायदे से काम करती है उसको हम सराहें और जहां सरकार प्रेसीडेंट एड्रेस में कुछ चीजें भूल जांए उसको हम बतायें कि आपने ये चीजें छोड़ दी हैं। यह जाहिर है कि यह सरकार जिन हालत में बनी है उसे हम सब जानते हैं और जिन हालत में यह प्रेसीडेंट एड्रेस पढ़ा गया। यह भी हम जानते हैं। जल्दी जल्दी में चीजें तैयार हुई हैं। जाहिर है कि नेशनल एजेंडे को सामने रखकर यह प्रेसीडेंट एड्रेस तैयार किया गया है। मेरा इसमें सिर्फ एक ही मानना है और वह यह है कि नेशनल एजेंडा जो आज प्रेसीडेंट एड्रेस की शक्ल में यहां आया है उसमें बहुत कुछ चीजें रह गई हैं। उसमें खासतौर से कम्युनिलिज्म, जहां आपने यह कहा कि हम सेकुलर वेल्यू को कायम रखेंगे, लेकिन जहां कम्युनिलिज्म है उसको वहां कैसे रोकेंगे और बढ़ते हुए कास्टिज्म को कैसे रोकेंगे, इसका खुलासा इस प्रेसीडेंट एड्रेस में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिसम्बर को इस मुल्क में एक वाटर-शेड हुआ। इसके कारण तमाम चीजें बिगड़ती चली गई और मुल्क की हालत इतनी खराब हो गई कि शायद 1947 में भी इतनी नफरत शायद पैदा हुई हो। बाबरी मस्जिद को 6 दिसम्बर को जो गिराया उससे दोनों कम्युनिटीज के बीच बड़ी नफरत पैदा हुई। जिस वक्त मुल्क टूट रहा था तो मौलाना आजाद ने कहा था कि अफसोस इस बात का है कि पहले मुल्क टूटा और अब दिल टूट गया। 6 दिसम्बर के बाद इस मुल्क के दिलों का बंटवारा हुआ। आज यह जो सरकार बनी है इस सरकार ने यह वायदा किया था कि हम सेकुलर वेल्यूज को बहाल करेंगे। लेकिन इस सरकार के सामने बहुत सी मजबूरियां भी हैं। उनकी मजबूरी यह है कि उनका एक छपा हुए एजेंडा है..... और एक छिपा हुआ एजेंडा है। उस छिपे हुए एजेंडे से मुझे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। जहां तक अटल जी का सवाल है, मैं जाती तौर पर उनकी बहुत इज्जत और ऐहतराम करता हूं। मुझे हासिल है कि अभी जो गल्फ कंट्रीज में डेलीगेशन गया था उसमें मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला। उनकी बाहर बहुत इज्जत है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि बाहर के लोगों ने उनकी बहुत इज्जत की है। मैं अभी भी कहूंगा कि बाबरी मस्जिद को गिरवाने में या बाबरी मस्जिद का जो एक मूवमेंट विश्व-हिन्दू परिषद्, आर०एस०एस० और बजरंग दल ने चलाया था, शयाद अटल जी वक्तन-फवक्तन अपने आप को बहुत होशियारी के साथ उससे अलग करते रहते थे। लेकिन सवाल यह है कि अटल जी की मजबूरी, उनकी गवनरमेंट की मजबूरी यह है कि वह भी इतने मजबूर हो जाते हैं जब अपनी मर्जी से जसवंत सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं तो आर०एस०एस० के जनरल सेक्रेटरी सुदर्शन साहब जाते है...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नाम नहीं लीजिये। ...(**व्यवधान**)

श्री वसीम अहमदः चलिये, नाम नहीं लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपकी मर्जी है।

श्री वसीम अहमदः आर० एस० एस० के प्रेशर के बाद...(**व्यवधान**) मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि इस एजेंडे में कनसेंसस जनादेश...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आज़म साहब आप बीच में रनिंग कमेंटरी मत कीजिए।

श्री वसीम अहमदः जनादेश जो मिला है वह आप और हम जनाते है कि बी०जे०पी० को 179 सीटें मिली हैं लेकिन बी०जे०पी० ने मीडिया के जरिए, वियुअल के जरिये यह इम्प्रेशन दिया कि जैसे उनको 279 सीटें मिली हैं। यह जनादेश उनका नही है बल्कि उनके अलाइज का है और वह अलाइज बाहालाते मजबूरी उसमें आए। उसमें आने की वजह यह हुई कि इसमें कुछ गलतियां हमारी तरफ से हुई हैं, कुछ हमारे कांग्रेस के साथियों की तरफ से हुई, कुछ यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हुई जिसकी वहज से वह अलाइज़ आपकी तरफ से गये। उन अलाइज को मैं मुबारकबाद दूंगा इस बात के लिये कि उन्होंने कम से कम बी०जे०पी० का जो हेटर्ड एजेंडा था उसको नहीं माना चाहे वह आर्टिकल 370 हो या यूनीफार्म सिविल कोड हो या सरकारिया कमीशन पर पूरी बहस हो या इस किस्म की बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसकी वहज से बी०जे०पी० आगे बढ़ना चाहती थी। जैसे अयोध्या का इश्यु है इसमें समता पार्टी से ले कर लोक शक्ति और इनकी तमाम पार्टियां उसके खिलाफ

थी लेकिन बी०जे०पी० की मजबुरी यह है कि एक तरफ तो कहते हैं कि गवर्नमेंट हम इस तरीके से चलाएंगे लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के हर लेबल पर, हर जिले पर आर०एस०एस० नफरत फैलाने का काम कर रहा है। अभी परसों 29 मार्च को अलीगढ़ की एक स्टोरी छपी है, युवराज झुमरे साहब की इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी है जिसमें यह कहा गया है कि वी०एच०पी० 5 अप्रैल से अयोध्या में इनिशियल कंस्ट्रकक्शन सेरेमनी शुरु करेगी। यह सब बातें इतनी खतरे की हो रही हैं कि इनसे हमें डर लगता है कि यह छपा हुआ एजेंडा कही पीछे न रह जाए और जो छिपा हुआ एजेंडा है, वह कहीं आगे न बढ़ जाए। हमें डर लग रहा है इन चीजों से। अभी अलीगढ़ के अंदर 29 मार्च को 'अमर उजाला' के अंदर दीन दयाल उपाध्याय के मिस्टर महेन्द्र साहब हैं उंहेंने यह कहा है कि मुसलमान जिनके पूर्वज हिन्दू थे हम उनको फिर से हिन्दू बनाने की बात करेंग। यह बातें पहली बार जब से यह सरकार आई है सामने आई हैं। चाहे बजरंग दल हो चाहे वी०एच०पी० हो या आर०एस०एस० हो अपने अपने तरीके से जो इनका हेटर्ड एजेंडा है, उसको बी०जे०पी० के उन तमाम लोगों के जरिये फैलाना चाहती है। हमें खतरा लगता है बी०जे०पी० ने अपने पास वह तीन पोर्टफोलियो रखे हैं—एच०आर०डी, इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग और मिनिस्टरी आफ होम जैसे वह पूरे सिस्टम पर बैठना चाहते हैं। अभी एक चेहरा है अटल जी प्राइम मिनिस्टर है तो अटल जी उस चीज को लागू नहीं होने देंगे। यह मुझे उम्मीद है। लेकिन यह जो मिनिस्ट्रीज है, इनके जरिये सिस्टम पर ऐसे लोग बैठ जाएंगे जिससे आइंदा नफरत का जहर फैले। इस मुल्क में एक खास कल्चर को तरबीयत मिले। इस मुल्क का मल्टीकल्चर है, इस मुल्क में कितनी जबानें हैं और यह मुल्क गंगा-जमीन तहजीब का मुल्क है। यह मुल्क एक कल्चर का मुल्क नहीं है बल्कि यह मुल्क है हजारों साल की बनी हुई तहजीब का। उस तहजीब को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो हम इस मुल्क को मजबूत करने का काम करेंगे। उपसभाध्यक्ष जी, मैंने और भी बहुत से अमेंडमेंट पेश किये थे। लेकिन बदकिस्मती मेरी यह है कि आज मुझे हाउस में उस वक्त बोलने का मौका मिल रहा है जब न यहां मीडिया है न यहां कोई सुनने वाला है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मीडिया है।

श्री वसीम अहमद: वह मुझे मालूम है। मैं भी जानता हुए मीडिया को इतिफाक से। हमारे सीनियर साथी सिकंदर बख्त साहब है उस हाउस में, और कोई नहीं है। चलिये रिकार्ड पर कुछ आ जाएगा। चूंकि हम लोग तो अदर्स हैं तो हमारे साथ बिल्कुल एक गैरों जैसा बर्ताव किया गया है। हम उम्मीद करते थे कि हमें उस हाउस में एक ऐसे वक्त पर बोलने का मौका मिलेगा जब हम अपनी बात पूरी ईमानदरी के साथ रख सकेंगे जिसमें कोई हिप्पोक्रेसी नहीं होगी। जिसमें कोई मक्कारी नहीं होगी। हम दिल के साथ अपनी बात रखना चाहते थे। में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये कहना चाहता हूं...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): यह जरूर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा जिस तरह से चेयर परसन ने नाम पहले दिये, जिस तरह की लिस्ट हर एक से पूछकर दी उसी के अनुसार बिल्कुल ही कार्यवाही हुई है। आप नहीं भी थे क्योंकि आप कह गये थे इस वजह से मैंने इंतजार किया।

श्री वसीम अहमद: मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया। मेरे दो-तीन प्वाइंट्स रह गये हैं। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और क्रिमिनलाइजेशन के सवाल को लेकर है। अभी यू०पी० में जो कुछ हुआ है उसको आप जानते हैं। यह कौन-सा कन्सेंसस है कि आप बी०एस०पी० तोड़ें? मुलायम सिंह का मुकदमा पिछले तीन साल के अंदर कोर्ट के अंदर रजिस्टर भी न हो और एक ही रात के अंदर फैसला हो जाए। लोग इधर से उधर चले जाएं फिर आप कहें कन्सेंसस यह कौन-सा कन्सेंसस है यह कहने का तरीका है आज क्रिमिनल चाहे वह**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं देखिये अब you are exceeding your limits चाहे** हो you should not take names.

I think this is very unfair.

श्री वसीम अहमद: फिर क्या करूं साहब नाम न लूं?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नाम और इस तरह के नाम ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: जो व्यक्ति इस सदन में नहीं है...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): यह नाम हटा दीजिए और मैं आपसे कहूंगा ...**(व्यवधान)** आजम साहब मैं चेयर पर हूं। I will ensure that my instructions are carried out with the co-operation of the House. I must

make this very clear वसीम साहब बहुत ही समझदार और बहुत मंजे हुये हमारे सांसद हैं और वे जानते हैं, वे बहुत संतुलन से बात करते हैं। इसी वजह से अब वे समाप्त करने वाले हैं।

श्री वसीम अहमदः एक चीज मैंने कही थी कि हमारे मुल्क में फारेन मीडिया आ रहा है। फारेन मीडिया आए। लेकिन वह एक्स्चेंज आफ व्यूज आदि सब दुनिया में एक दूसरे को विजुअल्स के जरिये से दिखा रहा है हमारे मुल्क में हमारी एक कल्चर है। हमारी तहजीब है। उस कल्चर और तहजीब से हटकर अगर हम अपने मुल्क में फारेन मीडिया के जरिये यहां चीजें दिखाएंगे तो हमारी कल्चर पर इसका असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस पर भी हमें गौर करना चाहिये कि हम कोई चीज ऐसी न करें जिससे कि हमारे मुल्क के कल्चर पर असर पड़े।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब तो आप खत्म कर रहे हैं।

श्री वसीम अहमदः बिल्कुल। इसमें वायदे किये गये हैं यानी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये। माइनारिटीज के लिये। कोई बचा नहीं है जिसके लिये वयादे नहीं किये गये हों। लेकिन वायदे करते वक्त यह कहीं नहीं बताया गया है कि हम क्या करेंगे, न उसका कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम है। यह बिल्कुल ऐसी बात है कि खाने पर आपको इंवाइटेशन पर बुलाया जा रहा है लेकिन मीनू नहीं बताया जा रहा है बिल्कुल।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मीनू क्या आपको पहले से भेज दिया जाए?

श्री वसीम अहमदः कम से कम उसका कहीं इंडीकेशन तो हो...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बैठिए मैं पूछ रहा हूं कि किस तरह से ...**(व्यवधान)** क्योंकि आज डिनर है मगर वे जा रहे हैं। इस स्पीच के बाद चले न जाएं इस वहज से मैंने कहा कि मीनू उनके पास भिजवा दूं...**(व्यवधान)**

श्री वसीम अहमदः तो मैं यह कहना चाहता था कि आज ये तमाम बातें थीं। इसमें लेबर की बात है। लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल लेबर हमने छोड़ा। हमने इसमें एग्रीकल्चरल लेबर छोड़ा और हमारे मुल्क में जो दस्तकार लोग हैं उनके लिये कोई बात खुलकर नहीं हुई है कि हम उनके लिये क्या करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब आप समाप्त करें।

श्री वसीम अहमदः रिव्यु आफ द कांस्टीटयूशन? यह एक ऐसा नाजुक मसला है कि जिस मसले को लेकर अगर आपकी टू थर्ड मेजारिटी होती और आप एलाइड्स पर डिपेंडेंट नहीं होते—आपकी तो इस वक्त हालत यह है गवर्नमेंट की कि एक एक एम०पी० के लिये हैरान और परेशान है— उसके बाद कहते कि हम मुल्क के संविधान को बदलेंगे। हम मुल्क के संविधान को रेव्यू करेंगे। आइये दो-तिहाई बहुमत के साथ और इस मुल्क के अंदर अपनी बात कहिये। फिर उसके बाद कहिये कि हम इस संविधान को रेव्यू करना कहते है या बदलना चाहते हैं। यह तो फंडामेंट्ल राइट्स हैं। आप कैसे तमाम इसको कह सकते हैं कि हम संविधान को रेव्यु करेंगे? यह रेव्यु का सहारा लेकर आप संविधान को, जो संविधान हमारे उन विद्वानों ने बनाया जिसकी वहज से आज हम सब लोग यहां मौजूद हैं, इस मूल्क का हर गरीब आदमी, हर बेसहारा आदमी, चाहे वह अकलियतों का हो, चाहे वह वैकवर्ड हो, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट हो, उनकी तमाम चीजें इस कंस्टीट्यूशन में लिखी हुई हैं, आप चाहते क्या हैं मैं कुछ नहीं समझ पा रहा कि आखिर यह संविधान किस तरीके से इसको रेव्यू किया जाएगा। मेरा मानना है कि यह गवर्नमेंट को चाहिये कि इसको विदड्रा करे और कहिये कि जब हम दो-तिहाई बहुमत से आएंगे तब संविधान को रव्यू करनेकी बात करेंगे।

आखिर में मैं एक शेर पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

"हर घड़ी रास्ते नए तामीर के सोचा करें,
आओ हम सब मिल कर अपने देश की सेवा करें,
हर कदम सच्चाई और इखलाक की खातिर उठाएं,
इस तरह अपने अमल से मुल्क को जन्नत बनाएं।"

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Dr. Vizol. He is not there. Dr. Raja Ramanna. I do not see him here. Prof Y. K. Alagh.

SHRI YOGINDER K. ALAGH (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to speak for a few minutes on something which we seem to be neglecting which is the whole question of the short-run performance of the Indian Economy. I regret that there has been no discussion of this issue. The only thing which we have had is an official document in which we are told—three statements are made—(1) that the growth of the economy in the last year is going to be five per cent or less; (2) that agriculture has grown at a negative rate of two per cent; and (3) that industry has grown at the rate of 4.6 per cent. Now, these are facts and as a former Chairman of the National Income Advisory Committee, I cannot object to these facts. But they give no understanding or no impression to anybody that there is any understanding of the industry and the problem that the Indian economy is facing in the short-run and what is proposed to be done in the next few weeks or in the next few months. I think this is an extremely serious issue. To say that we have had a negative agricultural growth and in a way that justifies a low growth rate is very incorrect. If you look at the Indian economy. it has crossed the stage now when negative agricultural growth should necessarily mean a low growth rate of the economy. If you look at the last 12 years, there are many years in which we have had negative agricultural growth but the growth of the conomy has been six or seven per cent. To say that the manufacturing growth rate is 4.6 per cent is in a way under-estimating the crisis. The industrial growth rate is 4.6 per cent because the electrcity sector has grown at a rate of around 7.5 per cent. The manufacturing growth is, in fact, much lower than that. It is around 3.5 per cent and the crisis is just not being brought out.

I would like to say that there are three factors which need immediate attention and I hope that we will get some response from the Government on them. The first is that this is an economy which has been facing a very serious demand crisis, demand deficiency. Many of us had been saying that. I can give you quotations from my own speeches as well as for, so many other economist. Now, we have got a Budget which says that the Central Plan expenditure was budgetted at Rs. 91,839 crores. The revised estimate that is given to us is Rs. 81,000 crores. This means a shortfall of Rs. 10,000 crores in the Central Plan expenditure in a year when we have excess capacity.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): क्या सदन सहमत है कि लीडर आॅफ द हाउस कुछ समय के लिए बाहर चले जाएं?

श्री सिकन्दर बक्त: दो मिनट के लिए जाना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): All right.

†[نیتا سدن شری سکندر بخت:
دو منٹ کیلئے جانا چاہتا ہوں۔]

SHRI YOGINDER K. ALAGH: I am sorry that I am not catching his attention.

He is obvisously not interested in what I am saying.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): No, no. He is very much interested. He had asked Dr. Mahesh to take notes.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: All right. This is the first time in the last ten years that the Annual Plan shows a short fall of Rs. 10,000 crores. I regret that the hon. Leader of the House did not even have the time to listen to what I say.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKINATH CHATURVEDI): He has gone for a short while. He is coming back. Sometimes, there are compulsions when one naturally has to leave.

†[ ]Transliteration in Arabic Script

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Some of the important sectors which the Government talk about in terms of priorities, are the ones, where they have shown these great shortfalls, irrigation, watershed developments. These are areas which need immediate attention—restructuring of agricultural credit, investment in communication and investment in transport. Now, these are the areas which could have been given immdiate attention. We are not being given any indication of what attention is going to be paid to them, particularly if there are areas like the Advanced Irrigation Benefit Programme, where the Budget says that monies have not been spent, then what is it that is intended to be done? To say that it will be looked at after three months, is just not fair to this country because this would mean that the revival of the economy is being postponed for beyond the monsoon. Unless we mobilise right now, we are not going to get the revival of the economy in the next few weeks and months. There is, by now, an overwhelming evidence of excess capacity in the economy and I would request that there should be a response. Take, for example, the Narmada project. I am just giving you an instance where projects are being delayed. The Narmada project which is a Plan-approved project, and I must say that as a Member of Rajya Sabha from Gujarat, I have very strong objections to this, the opponents of the project are there in the International Commission. I would like to know as to what the Government is doing about this. Look at China on the other hand. China has nominated to the same Commission the person who is responsible for the three gorges project, who is a person whom I know and I have worked with him in the International Mekong River Commission. So, we taking these things in an extremely casual manner. We are being given no guidelines on this. The whole question of export needs immediate attention because of the East-Asian crisis. We Know that 40 per cent of our export goods in the field of agriculture go to East Asia. Because of their income crisis, there is a lack of demand there. We are facing much greater competition in West Asia. We have been given no guidelines as to what the thinking is on such issues. What do we plan to do in the next few weeks or months on these issues? Similar is the case with regard to the whole question of agriculture. Recently, the Swiss Economist, Gilbert Etienne, who is supposed to be one of the authorities on Asian Agriculture in the world, has given a warning that it is the neglect of agriculture which has been responsible for the East Asian meltdom. I would like to quote Etienne because I think it is a very topical warning. He says. "In china, Vietnam, South Asia as a whole, agriculture deserves much more public funds than has been the case. Hydraulic works are in poor shape due to decades of neglect. Basic research is not encouraged enough, seed renewal is inadequate, as well as use of chemical fertilizers and pesticides. So far these defects have been compensated by good to fair monsoons (except in Pakistan and Indonesia). What happens if there is a really nastly monsoon? The lamentations on poor agricultural policies will make headlines all over then while timely action could have been taken! In india, the warning issued in the early 1990s by experts like C.H. Hanumantha Rao, Bimal Jalan have not had much echo so far." These are the questions relating to public investment decline, tax policy and export policy. On the export front, you cannot in the short run, deny the exchange rate devaluation because with the very wide fluctuations, what is happening in the East Asian economies? You cannot devalue your exchange rate that much.

SHRI YOGINDER K. ALAGH (CONTD): It means that you have to have non-exchange rate, non-price policy for export growth. If you look at the CII data, you will find that most of the industries which are suffering are suffering because of lack of Government demand and lack of export demand. The real question is: What do they plan to do about all these issues? I regret that we

are not getting any indication on these serious matters. I hope we will get some response from the Government on these questions. I wish the President had been advised to convey to us the seriousness of the situation. For the Finance Ministry to give us these three sentences based on the CSO results and to expect us to believe that this is their understanding of the Indian economy is most unfair. We would like to have some understanding of what is going on in India and what they plan to do. This is not being done at all. I feel that if some information on the economic affairs of India is provided to us, it would help us to have a better understanding and to have a better informed debate on these questions. I would like to submit that it would be incorrect for us to wait up till May or June. I think the kind of situation that we fare facing needs some immediate response. That is why I am not getting into the long-term questions at all. There will be the Budget very soon. Therefore, I am not getting into those issues. I am only getting into the short-term issues which need immediate attention. I think if we neglect them, there will be a fairly serious loss of output and employment for the Indian economy which can be avoided by taking into account all these things. I would like to bring to your attention the great shortfall in public expenditure and the need to give immediate attention to policies on the export front. Something should be done in the agricultural sector before the monsoon so that we need not wait till October or November for the revivial of the economy. We should prepare now itself so that the mobilisation can be done before the monsoon and the economy gets going on. I wish the President had been advised to take up these issues. I would suggest that it is not too late to take up some of these issues and to give us a response. Thank you.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिन बातों की चर्चा नहीं हो सकी हैं; उन्हीं बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूं और संक्षेप में करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण के पैरा 23 में कहा है—"ग्रामीण भारत के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाओं को आगे बढाने के अलावा मेरी सरकार कारगर फसल बीमा नीतियां शुरू करके किसानों को आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी संरक्षण प्रदान करेगी"। मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी हमारे देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों का है और खासकर कपास, गन्ना, जूट, रबर, लाल मिर्च उत्पादन करने वाले किसान हैं। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब आप संरक्षण प्रदान करने की बात करते है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवंबर, 1997 से इस देश के कई राज्यों में, खासकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कपास उत्पादन करने वाले किसान कर्ज के बोझ से इस बुरी तरह फंस चुके हैं, उनकी फसलें प्राकृतिक आपदा के कारण मारी गई है और वे कर्ज से, सूद दर सूद से इतने दब गए है कि वे आत्महत्या कर रहे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गैर सरकारी, स्रोतों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश का जो तेलंगाना इलाका है उसके सात जिले हैं, उन सात जिलों और दूसरे इलाके में 300 सीमांत और छोटे किसानों ने आत्महत्या कर ली है और आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में भी वहां की सरकार ने यह कबूल किया है कि 150 सीमांत और छोटे किसान अपनी स्थिति से ऊबकर आत्महत्या कर चुके हैं। उसी तरह से कर्नाटक में 20 कपास उत्पादक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये तो सरकारी आंकड़े है। खास कर जो कपास उत्पादक किसान हैं, नवम्बर महीने से लेकर अभी तक हर रोज़ उनमें से कोई न कोई आत्महत्या कर रहा है। केरल के इलाके में और दूसरे राज्यों में जहां पर लोग रबड़ उत्पादन करते हैं, कुछ साल पहले तक उनको एक किलोग्राम रबड़ की कीमत 60-65 रूपए मिलती थी, जो अब घटकर 25 से 30 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। जब आप सुरक्षा की बात करते है और पिछले नवम्बर से इस तरह की आत्महत्या की घटनाएं जारी हैं तो मैं समझता था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन किसानों की सुरक्षा और उनको तत्काल राहत देने के लिए चर्चा की जानी चाहिए थी। मैं अभी भी चाहता हूं कि हमारी जो नई सरकार है वह उनको सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दे, उनको आत्महत्या करने से रोकने के लिए तत्काल आन्ध्र और कर्नाटक के किसानों को विशेष सहायता दे, उनके लिए विशेष कदम उठाए, यह मेरा सुझाव है। इसी तरह से गन्ना उत्पादक किसान हैं, रबड़ उत्पादक किसान हैं, जूट उत्पादक आदि अन्य किसान हैं, उनकी भी स्थिति खराब होती जा रही है।

सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योग को हम प्रोत्साहित करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले दिनों देश के कई राज्यों के कई हिस्सों में किसानों ने गन्ने को जला दिया और इस बात से हम और आप इन्कार नहीं कर सकते। यह इसलिए किया गया कि चीनी मिल मालिकों की तरफ उनकी जो बकाया राशि है, वह सरकार दिला नहीं पाती है। वहां किसान फसल बोता है तो उसमें उसकी कीमत लगती है, मेहनत लगती है लेकिन उनको कोई मेहनत मिलती नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह नई सरकार इस बात की गारंटी करें कि किसान को लाभप्रद कीमत देने के लिए यह कोई विशेष योजना चलाएगी और गारंटी करे कि इन किसानों की फसलों की उनको लाभप्रद कीमत प्रदान करेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि यह देश किसानों का, मजदूरों का देश है, इसलिए यह प्राथमिकताएं सरकार के सामने होनी चाहिए और इसका उल्लेख भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में होना चाहिए था, जो नहीं है, जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की है।

दूसरे, ग्रामीण आबादी में करीब एक तिहाई खेतिहर मजदूरों की संख्या है और पिछली सरकारें संसद के दोनों सदनों में आश्वासन करती रहीं कि खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून का बिल वे लाएंगी। पिछली संयुक्त मोर्चे की सरकार ने भी कहा था और उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने भी कहा था। इतनी बड़ी आबादी के लिए यह जो नई सरकार आई है, उसके द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने और विधेयक लाने की चर्चा अवश्य होनी चाहिए थी, जिसकी उपेक्षा की गई है। हम समझते हैं कि इस सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसकी उपेक्षा करके, कृषि के क्षेत्र में अगर आप खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा करते हैं, तो आप कृषि का विकास नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं कि इस सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी उपेक्षा करके आप कृषि का विकास नहीं कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में अगर आप खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा करते हैं तो आप कृषि का विकास नहीं कर सकते हैं और आपका दावा खोखला साबित होगा और आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अभी बाकी है कुछ? अभी तो आप समाप्त कर रहे थे।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आपने समाज के एक अंग महिलाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है। यह निःशुल्क शिक्षा अपने देश में अजीबोगरीब है। अभी मैट्रिक तक सारे देश में निःशुल्क शिक्षा है लेकिन फीस माफ कर देना, शुल्क माफ कर देना, यह निःशुल्क शिक्षा के माने नहीं है। हम अपने राज्य के बारे में आपको बता दें कि जो फीस लगती है, उससे ज्यादा शुल्क मिसलेनियस चार्जेज के नाम पर ले लिया जाता है। इस निःशुल्क शिक्षा से उन गरीबों, पिछड़ों, दलितों को कोई फायदा नहीं होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अपना राज मत बताइए, पब्लिकली।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: ये तो पब्लिक सीक्रेट है। अगर आपका कोई सीक्रेट एजेंडा है तो वह आप हम लोगों को बता दीजिए। हम तो कोई सीक्रेट रखते नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): कहीं दूसरे राज्य भी एजुकेशन के क्षेत्र में वह करने न लगें, इस वजह से कह रहा हूं।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: यह मैंने अपने राज्य के बारे में बताया। अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, यह मैं नहीं जानता लेकिन जिस बात को मैं सही तरीके से जानता हूं, उसको मैंने आपके सामने और सदन के सामने रखा है।

महोदय, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि 6 साल से 14 साल के बच्चे और बच्चियों के लिए संविधान लागू होने के 10 साल बाद उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। महोदय, आजकल हम लोग आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं लेकिन मुझे दर्द के साथ कहना पड़ रहा है और इस पर आपकी भी सम्मति होनी चाहिए पार्टी लाईन से ऊपर उठकर कि आज भी ये बच्चे और बच्चियां स्कूल, मदरसा या किसी पाठशाला में जाने की स्थिति में नहीं हैं। जब बच्चियां पढ़ेंगी ही नहीं तो महिलाएं स्नातक स्तर तक कैसे पहुंचेंगी?

महोदय, मेरा ख्याल है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की चर्चा होनी चाहिए थी। मैं इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सत्ता में आए हैं तो आप एक काम कीजिए जिससे

बड़ा ही भला होगा इस देश का और पूरे समाज का कि आप 6 से 14 साल के बच्चे और बच्चियों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके इस देश से निरक्षरता को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़िए, पूरा देश आपकी तारीफ करेगा।

हम आपकी नीयत और नीति पर शक इसलिए करते हैं कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी आप सत्ता में आए हैं तो सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि हम ही नहीं, बल्कि देश की जनता भी आपकी नीयत और नीति पर शक न करे। आप व्यवहार में अपने वायदों को अमली जामा कैसे पहनाते हैं, यह तो आने वाले दिनों में ही साबित हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

†[شری جلال الدین انصاری "بہار":
دھنیواد اپ ادھیکش مہودے -
راشٹرپتی کے ابھیبھاشن میں جن
باتوں کی چرچہ نہیں ہو سکی ہے انہی باتوں
کی میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں اور سنکشیپ
میں کرنا چاہتا ہوں - راشٹرپتی جی نے
اپنے ابھیبھاشن کے پیرا ۲۳ میں کہا
ہے ..." گرامیں بھارت کے جو مکھی
وکاس کے لئے یوجناؤں کو آگے
بڑھانے کے علاوہ میری سرکار کارگر
فصل بیمہ نیتیاں شروع کر کے کسانوں
کو آکاسمیک - پراکرتیک - آپ داوس
کی استھتی میں بھی سنرکشن پردان
کرے گی - میں آپکے مادھیم سے اس مانیہ
سدن کا دھیان آکرشت کرانا چاہتا
ہوں کہ ابھی ہمارے دیش کی آبادی کا

†[ ]Transliteration in Arabic Script

سب سے بڑا حصّہ کسانوں کا ہے
اور خاصکر کپاس - گنّا - جوٹ - ربر -
لال مرچ - اتپادن کرنے والے کسان
ہیں - انکی استھتی بہت ہی دینیہ
ہے - جب آسنرکشن پردان کرنے کی
بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا
ہوں کہ نو مبر ۱۹۹۷ سے اس دیش کے
کئی راجیوں میں خاص کر آندھرا پردیش
اور کرناٹک میں کپاس کا اتپادن کرنے والے
کسان قرضوں کے بوجھ سے اس بری طرح
پھنس چکے ہیں انکی فصلیں پراکرتیک
آپدائے کارن ماری گئی ہیں اور وہ
قرض سے سود در سود اتنے دب گئے
ہیں کہ وہ آتم ہتیا کر رہے ہیں اور
میں آپکو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیر سرکاری
ذرائع کے مطابق آندھرا پردیش کا جو
تلنگانہ علاقہ ہے اسکے سات ضلع ہیں
ان سات ضلعوں اور دوسرے علاقوں
میں ۳۰۰ سیمانت اور چھوٹے کسانوں
نے آتم ہتیا کر لی ہے - اور ادھر پردیش
ودھان سبھا میں بھی وہاں کی سرکار
نے یہ قبول کیا ہے کہ ۵۰ سیمانت اور
چھوٹے کسان اپنی استھتی سے اوپر اٹھ کر
آتم ہتیا کر چکے ہیں اسی طرح سے کرناٹک
میں ۲۰ کپاس اتپادک کسانوں نے

خراب ہوتی جارہی ہے۔ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ گرامین الکشیتر میں گرشی پر آدھارت ادیوگ کو ہم پروتساہت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں دیش کے کئی راجیوں میں کے کئی حصوں میں کسانوں نے گنے کو جلا دیا اور اس بات سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے یہ اسلئے کیا گیا ہے کہ چینی مل مالکوں کی طرف سے انکی جو بقایا راشی ہے وہ سرکار دلا نہیں پاتی ہے۔ وہاں کسان فصل بوتا ہے تو اسمیں اسکی قیمت لگتی ہے۔ محنت لگتی ہے انکو کوئی محنت ملتی نہیں ہے۔ اسلئے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ نئی سرکار اس بات کی گارنٹی کرے کہ کسان کو لاگت پر قیمت دینے کیلئے یہ کوئی وشیش یوجنا چلائے گی۔ اور گارنٹی کرے کہ ان کسانوں کی لاگت پر قیمت پردان کرے گی۔

اب سبھا ادھیکش مہودے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیش کسانوں کا۔ مزدوروں کا دیش ہے اسلئے یہ پرا تھمکتا ئیں سرکار کے سامنے ہونی چاہیئں اور اسکا ذکر بھی راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں ہونا چاہیئے تھا آتم ہتیہ کر رہی ہے یہ تو سرکاری آنکڑوں میں خاصکر جو کپاس اتپادک کسان ہیں نومبر کے مہینے سے لیکر ابھی تک ہر روز ان میں سے کوئی نہ کوئی آتم ہتیہ کر رہا ہے۔ ودربھ کے علاقہ میں اور دوسرے راجیوں میں جہاں پر لوگ ربر اتپادن کرتے ہیں کچھ سال پہلے تک انکو ایک کلو گرام ربر کی قیمت ۶۰-۶۵ روپیہ ملتی تھی جو اب گھٹ کر ۲۵ سے ۳۰ روپیہ پر تی کلو گرام ہو گئی ہے۔ اب آپ سرکشا کی بات کرتے ہیں اور پچھلے نو مہینے سے اس طرح کی آتم ہتیہ کی گھٹنائیں جاری ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں ان کسانوں کو سرکشا اور انکو فوراً راحت دینے کیلئے چرچہ کی جانی چاہیئے تھی۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ ہماری جو نئی سرکار ہے وہ انکو سرکشا پردان کرنے کا آشواسن دے۔ انکو آتم ہتیہ سے روکنے کیلئے تتکال آندھرا اور کرناٹک کے کسانوں کو خاص کر رعایت کرے۔ اسکے لئے وشیش قدم اٹھائے۔ یہ میرا سجھاؤ ہے۔ اسطرح سے گنا اتپادک کسان ہیں۔ ربر اتپادک کسان ہیں۔ جوٹ اتپادک وغیرہ کے کسان ہیں۔ انکی بھی اسمتی

کر سکتے ہیں - کرشی کے سیکٹر میں اگر آپ کھیتی ہر مزدوروں کی اپیکشا کرتے ہیں تو آپ کرشی کا وکاس نہیں کر سکتے ہیں - اور آپکا دعویٰ مجھے معقول ثابت ہوگا اور آپ اس میں سفلتا حاصل نہیں کر سکتے ہیں - تیسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ... "مداخلت" ....

اپ سبھا ادھیکش "شری تروکی ناتھ چترویدی": ابھی باقی ہے کچھ - ابھی تو آپ سماپت کر رہے تھے -

شری جلال الدین انصاری: اپ سبھا ادھیکش مہودے - میں آپکا زیادہ وقت نہیں لونگا - مجھے خوشی ہے کہ اشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں آپ نے سماج کے ایک انگ مہیلاؤں کو سماتک ستر تک نیشلاک شکشا دینے کی بات کہی ہے - یہ نیشلاک شکشا اپنے دیش میں عجیب و غریب ہے - ابھی میٹرک تک سارے دیش میں نیشلاک شکشا ہے - لیکن فیس معاف کر دینا - شلاک معاف کر دینا - یہ نشلاک شکشا کے معنی نہیں ہیں - ہم اپنے راجیہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جو فیس لگتی ہے اس سے زیادہ شلاک مسلینیس چار چیز کے نام پر لیا جاتا ہے اس نیشلاک شکشا سے جو نہیں ہے - جسکی چرچہ ہم نے آپکے سامنے کی ہے -

دوسرے گرامیں آبادی میں ایک تہائی کھیتی ہر مزدوروں کی سنکھیا ہے اور پچھلی سرکاریں سنسد کے دونوں سدنوں میں آشوا سن کرتی رہیں کہ کھیتی ہر مزدوروں کے لئے لیگسلیٹو یہ قانون کا بل وہ لائیں گی - پچھلی سنیکت مورچہ کی سرکار نے بھی کہا تھا اور اس سے پہلے کانگریس کی سرکار نے بھی کہا تھا - اتنی بڑی آبادی کیلئے یہ جو نئی سرکار آئی ہے اسکے ذریعہ راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں کھیتی ہر مزدوروں کے لئے لیگسلیٹو یہ قانون بنانے اور دیکھ ریکھ کرنے کی چرچہ ضرور ہونی چاہئے تھی اسکی اپیکشا کی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کو اس پر خاص دھیان دینا چاہئے - یہ ایک بہت بڑا اکسیشن ہے اسکی اپیکشا کر کے کرشی کے اکسیشن میں اگر آپ کھیتی ہر مزدوروں کی اپیکشا کرتے ہیں آپ کرشی کا وکاس نہیں کر سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سرکار کو اس پر وشیش دھیان دینا چاہئے - یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کی اپیکشا کر کے آپ کرشی کا وکاس نہیں

آجکل ہم لوگ آزادی کی ۵۰ ویں سالگرہ منا رہے ہیں لیکن مجھے درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور اس پر آپکا بھی اتفاق ہونا چاہیئے پارٹی لائن سے اوپر اٹھکر کہ آج بھی بہت سے بچے اور بچیاں اسکول۔ مدرسہ یا کسی پاٹھ شالہ میں جانے کی استھتی میں نہیں ہیں جب بچیاں پڑھینگی ہی نہیں تو ہمیلائیں سمناتک استر تک کیسے پہنچیں گی۔

مہودے۔ میرا خیال ہے کہ راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن میں پرا تھمیک شکشا کو نی شلک اور انیوارہ بنانے کی چرچہ ہونی چاہیئے تھی۔ میں اس سرکار سے مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی ۵۰ ویں سالگرہ کے موقع پر آپ سنسد میں آئے ہیں تو آپ ایک کام کیجیئے جس سے بڑا ہی بھلا ہوگا اس دیش کا اور پورے سماج کا۔ کہ آپ ۶ سے ۱۴ سال کے بچے اور بچیوں کیلئے ضروری اور بلا فیس کی تعلیم کی ویوستھا کرکے اس دیش سے جہالت کو ختم کرنے کی دشا میں آگے بڑھیئے۔ پورا دیش آپکی تعریف کرے گا۔ ہم آپکی نیت اور نیتی پر شک اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کہتے کچھ ان غریبوں۔ پچھڑوں۔ دلتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔

اپ سبھاادھیکش: اپنا پرشن بتایئے پبلیکلی۔

شری جلال الدین انصاری: یہ تو پبلک سیکریٹ ہے۔ اگر آپکا کوئی سیکریٹ ایجنڈا ہے تو وہ آپ ہم لوگوں کو بتایئے۔ ہم تو کوئی سیکریٹ رکھتے نہیں ہیں۔

اپ سبھاادھیکش: کہیں دوسرے راجیہ بھی ایجوکیشن کے اکشیتر میں وہ نہ کرنے لگیں۔ اسوجہ سے کہہ رہا ہوں۔

شری جلال الدین انصاری: یہ میں نے اپنے راجیہ کے بارے میں بتایا۔ اب راجستھان۔ اتر پردیش مہاراشٹر کی کیا استھتی ہے۔ یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن جس بات کو میں صحیح طریقے سے جانتا ہوں اسکو میں نے آپکے سامنے رکھا ہے۔

مہودے۔ بھارتیہ سمودھان میں راجیہ کی نیتی نردیشک سدھانتوں میں اس بات کی ویوستھا کی گئی تھی کہ ۶ سال سے ۱۴ سال کے بچے اور بچیوں کے لئے سمودھان لاگو ہونے کے ۱۰ سال بعد انکے لئے بغیر فیس کے ضروری تعلیم کی ویوستھا کی جائیگی۔ مہودے

ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ابھی آپ بیٹھ
میں آئے ہیں تو بیٹھ میں آنے کے بعد
کچھ ایسا کام کیجئے تاکہ ہم ہی نہیں بلکہ
دیش کی جنتا بھی آپکی نیت اور نیتی
پر شک نہ کرے۔ آپ ویودھار میں
اپنے وعدوں کو عملی جامہ کیسے پہناتے
ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی ثابت
ہو سکے گا۔ ان لفظوں کے ساتھ میں
آپکا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپنے مجھے
اس اہم بحث میں بولنے کا موقع دیا۔
ختم شد۔

SHRI W. ANGOU SINGH (Manipur): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the debate on the Motion of Thanks on the President's Address. Sir, my speech will be very brief.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Thank you. That is what the hon. Members want. Otherwise, there won't be many Members to listen, except you and me.

SHRI W. ANGOU SINGH: Sir, I would speak about some of the issues which have not been included in the Address of the President. There is no mention of the problem being faced by the North-Eastern region. Mr. Vice-Chairman, Sir, you know that the problem of insurgent movement in the North-East is a critical one. Sir, the 36th Report of the Committee of the Home Ministry on insurgent situation in the North-Eastern region presented on 26th February, 1997 to Rajya Sabha and Lok Sabha states, "The insurgents are supported and contributed from across the border considerably and the Manipur, Nagaland, Assam and some parts of Tripura are seriously affected." Sir, there is no mention of the measures which are being taken to solve this problem. At least, the Central Government must think it over to have a political dialogue with different insurgent groups which are now operating in the North-Eastern region. Sir, as for Manipur, there are 18 insurgent groups in the valley area, including the ULF. In the hill areas, there is NSCN which is now operating in Nagaland as well in most parts of the hill areas of the North-East. The ULFA is operating in Assam. All these problems should be considered seriously, specially by the Central Government.

The Address of the President has not made any mention of these problems. So, this was the first point which I wanted to raise.

My second point is that the infrastructure development or the resource mobilisation is very difficult in the North-Eastern region because there is a restriction about entry of tourists in this region as the Inner Land Permit has already been imposed there. It is still continuing there. Therefore, the people of this region feel that they are being considered as second class citizens by the Centre. This is one of the main feelings which is there is in the minds of the younger generation. Sir, There is no mention of removal of the restriction of Inner Land Permit in the Address of the President.

Sir, the other problem which is being faced by this region is of border Development Programme. The Home Ministry Committee's report clearly states that the problem of the North-Eastern States is not less than that of the Jammu and Kashmir problem. This region has 1,126 kilometre long international border with China, 487 kilometre long border with Bhutan, 1,643 kilometre long border with Myanmar and 1,187 kilometre long border with Bangladesh.

But now the problem is that the people living in the border areas are the poorest

of the poor. Even then, the Government has not taken up any programme for border area development in this region. During the regime of the United Front Government, I myself raised an issue about taking up a programme for border area development. The then Government had assured me that this would be done in the coming Plan, but there was not any mention about it in the President's Address. All those people who are the poorest of the poor, for their livelihood, are forced to render help to the smugglers and the insurgents to cross the border. I feel that the Centre is allowing this situation to continue. A solution to this problem also does not any mention in the President's Address.

Taking advantage of my participation in the discussion, I now want to mention about a problem regarding the reimbursement of security-related expenditure in my State, Manipur. This has already been submitted to the Government of India for reimbursement. The same has not been reimbursement even after a lapse of four or five years. The other States like Nagaland and Assam have already been reimbursement. There is some sort of a step-motherly treatment being meted out to the State of Manipur. That is also one of the causes for discontentment among the people of Manipur because the money which has already been used for security purposes is from the development side.

Another point which I want to raise here is about a separate Ministry for North-East. I myself raised this issue in the House on 1.8.96. I read it in some of the newspapers that the BJP and its Allies Government would consider this issue. But this has not been mentioned in the President's Address. So, I have no faith that the present BJP and its Allies Government will do something for the North-East. I don't want to take much time of the House. The Vice-Chairman has been looking at me. I am also not conversant with it. I request the Government that instead of doing lip-service from the point of view of popularity, it should take some specific measures to remove such type of neglect of the backward areas. It is this sentiment of discontent which gives rise to insurgency in those areas. If the present Government could do something on democratic lines, only then the Prime Minister Atal Behari Vajpayee's concept of consensus would be acceptable. If it is not, it will only be taken like the Hindi prover: "मुंह में राम, बगल में छुरी"। That will not strengthen the integrity of our country. Thank you, Sir.

Dr. B.B. DUTTA (Nominated): Sir, I would like to draw the attention of the Leader of the House...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You can do so when you speak here. ...*(Interruptions)*...

DR. B.B. DUTTA: Sir, the hon. Member has mentioned that the Home Ministry is collecting money from the States for mobilisation of police, CRPF and all that. This is what he referred to. ...*(Interruptions)*... In Punjab ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You can elaborate it when your chance to speak comes. ...*(Interruptions)*... We are very few Members left here. The Chairman was good enough to extend the sitting of this House on our request. It is not a good reflection on us that so very few Members are present and some of the Members who gave their names, somehow or the other, are not present here. The Members who are here have seriously attended to their responsibility today. My only request is that some of us who are left here may sit here to listen to those Members who have not yet spoken. As I said, the staff of the Secretariat is also here. A dinner has also been arranged. That is why I do not want to read out all the names because I find only a few Members are present. ...*(Interruptions)*... Now I ask Mr. V.P. Duraisamy to speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): Sir, I have been waiting for the last four days for speaking. I am very fortunate that I have been speaking when you are in the Chair. Sir, on behalf of my party, the DMK, I offer my warmest felicitations to hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayeeji, for winning the Vote of Confidence. The DMK Government under the able and dynamic leadership of Dr. Kalignar has presented a remarkable Budget on 27th March. He is giving a boost to the downtrodden communities, especially the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He is implementing far-reaching model programmes and welfare schemes. The Government of Tamil Nadu is giving high priority to agricultural sector. The agriculturists in Tamil Nadu have increased the production of foodgrains from 74 lakh tonnes to 95 lakh tonnes. If the Cauvery Water Tribunal Award had been implemented earlier, we would have produced more than that and would have been able to supply it to the neighbouring States...(*Interruptions*)... Yes, including Karnataka also. I have gone through the National Agenda as well as the Presidential Address. Both of them have not mentioned anything about the implementation of the Cauvery Water Tribunal Award. Sir, in the President's Address I find that it has not been mentioned very clearly. The Address only says, "A National Water Policy which will provide for effective and prompt settlement of disputes and their time-bound implementation will be evolved." It has not mentioned anything specifically about the implementation of the Cauvery Water Tribunal Award.

Cauvery water is the backbone to the Tamil Nadu agricultural community. I must also bring to the notice of the House that our party - D.M.K. - Parliamentary Group Leader, Shri Murasoli Maran, as Minister of Industries in the United Front Government for 21 months, formulated a transparent policy to attract foreign direct investment. This has paid ample dividends, as may be seen from the figures of the foreign direct investment approvals and foreign direct investment inflow. The hon. Prime Minister has announced that his Government is committed to create three new States: Uttaranchal in U.P., Vananchal in Bihar and Chattisgarh in M.P. Yesterday I have seen a news item in *The Hindu*. It was published that the Union Government is going to give higher priority to give statehood for Delhi. We are also welcoming wholeheartedly formation of new States for the betterment of the people and to approach the officers for getting benefits. Sir, giving Statehood to Pondicherry is a long pending matter. The hon. Chairman also knows very well that our beloved brother, Shri Narayanasamy, has also requested the Government so many times for giving Statehood to Pondicherry. It has been neglected. I request that it has to be considered favourably and Pondicherry should be given Statehood very urgently.

The National Agenda also mentioned that the interests of the SC/STs and OBCs will be adequately safeguarded through appropriate legal, executive and social efforts, by giving large scale education and employment opportunities. I understand that this Government is committed to providing compulsory education up to school level by adopting the reservation policy. The hon. Vice Chairman also knows very well as a senior-most I.A.S.-officer-turned-politician that it is no use giving compulsory education up to school level unless the Government comes forward to give job opportunities on communal basis. The Chairman also knows very the recial leader, Thanthai Periyar, is the cause for bringing the First Constitutional Amendment. The then Prime Minister, Pandit Nehruji, also agreed with Thanthai Periyar and permitted bringing the Constitutional amendment to give employment opportunities to provide education to SC/STs and OBCs on community basis. The National Agenda and the Presidential Address have not mentioned anything. We are very much afraid whether this Government is going to extend the reservation - 69% - further.

We have a great apprehension in our minds that we are going to be deprived of our rights.

The other day, the learned Sangmaji, former Speaker of the Lok Sabha, while speaking in the Lok Sabha...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): We are not supposed to refer to the proceedings of the other House. You can say some hon. Member in the other House.

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamilnadu): He stated that many of the vacancies reserved for SC/STs and OBCs are filled from the other communities. How can we expect social justice from the Government? Where is the guarantee to believe that the Government is going to give social justice? Here, I request that the Government should see to it that the posts reserved for SC/STs and OBCs are filled only by SC/STs and OBC people.

Sir, in spite of the mention about genuine secularism in the National Agenda, there is a wide-spread apprehension in the minds of the people, particularly, the minorities, seeking protection. I have read the hon. Prime Minister's speech in Lucknow where he requested the people and gave an assurance to the people not to have fears over religion, caste, colour or creed and sex. But, the minorities still have apprehensions whether the BJP Government will protect the rights of the minorities, particularly, the Christians and the Muslims. The attitude of this Government should change. My party welcomes the recommendations of the Sarkaria Commission. The Sarkaria Commission was constituted by the then Prime Minister, Shri V.P. Singh, under the chairmanship of Justice Sarkaria, to go into the Article 226, to settle down the problem of inter-State water problem. So many committees have been constituted, but none of their recommendations have been implemented. If this Government is really interested to implement the recommendations of the Sarkaria Commission, then the DMK party wholeheartedly welcomes it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): About which Commission are you talking?

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, I am referring to Sarkaria Commission, constituted to settle down the problem of inter-State water problems.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Probably, you may be referring to some other Commission, not Sarkaria Commission. Anyway, please continue.

SHRI V.P. DURAISAMY: No, Sir, I am referring to the Sarkaria Commission only.

Sir, this Government has assured the people that, under any circumstances, it would not misuse Article 356. The Prime Minister of India, Shri Vajpayeeji, is the tallest personality in India. He is a great poet. He is a great orator. He is a politicial *sadhu*. He is a great orator and writer like our leader, Dr. Kalignar. He has nominated a Law Minister from Tamil Nadu. I am not making any allegations...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please do not refer to it. He is a Member of the other House...(*Interruptions*)...

SHRI V.P. DURAISAMY: He has appointed the Law Minister ignoring the party differences. We all respect the hon. Prime Minister. Immediately after assuming the office he gave a statement to the Press in Chennai that all the cases related to Jayalalitha are foisted. He wanted to re-examine those cases. Have you ever seen a Law Minister, in the last 50 years of independence, who has interfered with the judiciary. The judiciary is an independent body. It is the third pillar of the democratic setup. How can a Union Law Minister interfere in the judiciary? He should be very fair and neutral. I am not going to hurt anybody's feelings. But, Tamil Nadu Government denied all those allegations in the State Assembly. It is for the first time that a non-law graduate has been made a Union Minister for Law

& Justice. "L" stands for 'law', and "J" stands for what I don't know. Why is he saying that he wants to re-examine all the 20 cases, which are pending? Sir, the BJP Government...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think, it is time for you to wind up now.

SHRI V.P. DURAISAMY: Yes, Sir. Before me many hon. Members have spoken on Article 370, construction of temple, common civil code, and so on, but I do not want to touch all those points again and waste the valuable time of the House. Sir, this Government should run for the full term. We are not against that...(*Interruptions*)...But, at the same time, the Prime Minister said to the Press that he would not yield to anybody's pressure.

Sir, some persons have been taken into the Cabinet. These persons wanted to have portfolios of their choice. But Sir, we should allow the law to take its own course. The Government should not succumb, under any circumstances, to any pressure from outside.

At the time of election of the Speaker, the ruling coalition mooted the idea that the person for the office of the Speaker should be chosen by consensus among all the political parties. But we do not know what made the Government to choose a Member from the Telugu Desam Party as the nominee for the post of Speaker. The BJP Government should strive for consensus, at least, on important national issues.

As far as terrorism is concerned, my friends from the AIADMK raised the issue of bomb blasts in Tamil Nadu.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): They are not here. Why are you referring to them? They may suddenly appear. Why should you enter into a controversy?

SHRI V.P. DURAISAMY: Regarding the bomb blasts in Tamil Nadu, the hon. Home Minister said yesterday in the other House that terrorism was not the problem of a particular State. The Home Minister made a statement yesterday in the other House. Sir, terrorism is not confinded to just one or two States. It is a national problem. We have seen what happened in Tripura. The Health Minister of the State was shot dead by terrorists. What about Maharashtra? There were bomb blasts at the time of elections. Such incidents have taken place in various States. Even in Delhi, which is under the BJP, within a year, there have been twenty-three bomb blasts.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You have made your point. I think you should wind up.

SHRI V.P. DURAISAMY: Now, we do not say that the Maharashtra Government or the Delhi Government should be dismissed. It is not fair. In this connection, I am glad to note that the Home Minister has come forward to assist, in all possible, ways, in curbing such incidents and in nabbing the culprits who are responsible for these bomb blasts.

Lastly, Sir, I want to point out one glaring thing in the President's Address. We are in the Golden Jubilee Year of India's Independence. I do not know whether it has been mentioned in the President's Address mistakenly or wilfully. Now, Sir, we call Gandhiji as the Father of the Nation. In our school days, all our teachers have told us that Mahatama Gandhi should be called the Father of the Nation. We call him, 'Desa Pita' in Tamil. When this is so, it is strange that the President's Address refers to him as 'Mahatama Gandhi'. They have not said 'Desa Pita' or 'Father of the Nation'. He has been referred to as an ordinary man.

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Duraisamy, 'Mahatma Gandhi' itself signifies that he is great. Anyway, please conclude now.

SHRI V.P. DURAISAMY: Why should they fight shy of referring to him as 'Desa Pita'?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): It is all right.

SHRI V.P. DURAISAMY: I am just concluding.

Sir, I have seen the National Agenda as well as the President's Address. Both of them contain nothing. It is only 'old wine in a new bottle.' This is all I have to say.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Now, we have four Members left who have to speak. Two other Members—Shri Miri and Shri Solanki—have withdrawn their names. First, I would call upon Shri H. Hanumanthappa.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, I am not speaking.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Okay. Dr. B.B. Dutta. After him, it will be Shri Mohd. Azam Khan, followed by Shri Brahma Kumar Bhatt. Now, Dr. B.B. Dutta, please.

DR.B.B. DUTTA: Thank you, Mr. Vice-Chairman. The House is nearly empty and the time is short. Therefore, I would confine myself to three major points which have been mentioned in the President's Address. But before I do that, I would like to invite the attention of the Leader of the House....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Sikander Bakht Saheb, he is inviting your attention.

SHRI SIKANDER BAKHT: Yes.

DR. B.B. DUTTA: Mr. Angou Singh mentioned in his speech about the despatch of additional security forces—CRPF and all that—to the various insurgency-stricken States. Now, the Home Ministry reimburses the expenditure incurred. In respect of Punjab, they gave some concessions. Loan waiver was also declared. Then the North-Eastern States, particularly Assam, demanded that this should apply to them also. So, some progress has been made in that direction also. Now, if you cover one State in the North-East, there is no reason why you should not cover Manipur and Nagaland, which are gravely under the impact of insurgency.

My second point is this. I do not understand why the Home Ministry is so meticulous in putting the burdens of the expenditure incurred by the military wing, when they come to the aid of the civilian administration and operate in certain areas on the military Accounts. The entire amount so incurred is spent from the military budget. Sir, I would like to bring to your notice that we have given too little to the military wing and that the military is spending Rs. 2,500 crores every year on this duty alone in aid of civilian administration, which is not their job. I, as a member of Parliament, take exception to this and bring this to your notice.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI SIKANDER BAKHT): Excuse me, Sir. May I request the hon. Member to kindly write to me a letter on this subject? I would be thankful to him.

DR. B.B. GUPTA: All right.

Sir, in paragraph 28 of the President's address, the President has said: "My Government will initiate action to create three States and also make Delhi as a full fledged State." this is what he said, I, for one, am not against making small or large States in India, whatever way you

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI), *in the Chair.*

look at. If the number of States are increased, I am not bothered about it. But, I am very much bothered about one point, because I come from an area where in the history of India State-making has been stretched to an illogical extent. We have discarded the principle of language as the criterion of State-making. The SRC visited the North-East and recommended that Assam should be a composite State. This was done because of regional security, Assam being a

sensitive border area. By 1971, through the North-Eastern Reorganisation Act, we had discarded the security criteria, we have discarded the economic criterion and we have discarded the ethnic criterion. What have we not discarded? You have created States because you found that you are in such a situation that you are dictated by sheer expediency.

Sir, I come from an area where small States have been created. If the assumption of the present Government is that small State is a good State for efficient governance, then I tell you that we live in small States. Before you venture in to further State-making, is it not fair that you make an assessment of the situation and see what has happened from 1971 to 1998? You should take lessons from the past instead of taking that prevail in the Centre, So, I would request the present Government that before going ahead to make States, kindly take lessons and arrive at a sound principle or criterion, which will guide State-making. At present there are 31 demands pending before the Government of India. You cannot concede all those demands. Some people in the Home Ministry made an exercise and said that 12 or 13 demands may be considered feasible to be met. These excercise should be seriously made and you should find out how many States you can give in which areas and how many you have to reject for what reasons. If you go in a cavalier fashion, if you give a State here today and a State there tomorrow because of political compulsions, because of today's political expendiencies, it may lead you in trouble tomorrow or the day after tomorrow. This is not fair. I am not saying that you should not give. But we have found that in the small State, when the constituency becomes small, localism creates a big problem. Way back in the late sixties—ask the Home Ministry officials—they made some exercises about the repercussions of the creation of small constituencies. When in a small State you make 60 constituencies under constitutional compulsions, it was found that elections could never be held in a small constituency on national issue. National issues are never discussed. An MLA tender to become a tout. He has to get them cement and what not. He cant function as a legislator. If national issues, macro issues, are to be projected, then the size of the constituency, the size of the State, the mix of the pupulation, everything is important and it has got a bearing to the eventual stability or instability that prevails in the Centre. So, I would request you to go ahead, to put in a serious thought, a serious study; and then, in a cool-headed way, with a sound policy, go ahead and create as many States as possible and then put an end to that. State-making is very simple in the Indian Constitution; by a simple majority you can create States; the process is very open. It should be made more restrictive, more stringent. Suppose you go in for three particular States. Tomorrow, you create demands for six States in six different areas. There will be protests. Then you are required to send the CRPF and paramilitary forces and what not. So, think over it.

My second point is this. I draw your attention to this particularly. This is about the nuclear policy. From my party, from other parties, from very important and experienced leaders, comments have come. I am a very humble man, a very momentous decisions in the field. State-making is not a child's play. You are tinkering with the structure of the polity of India. You are, by your actions, affecting the Centre-State relations. You are affecting the stability of instability unimportant Member in this House. But I have got my own opinions. As far as I have studied the situation, we have got certain compulsions. We have the bitter experience of our conflicts with Pakistan. The Partition did not solve the problems. It compounded the problems. Those problems remain in a more intensified manner. They are becoming manifest every day and getting more compounded,

becoming more complex. Therefore, when I consider my security commitment, Pakistan is definitely a security threat. I cannot forget about it. China is emerging as a great power. It has an impact not only in South-East Asia and South Asia but in the entire region, globally also. We have to balance China. India, by her size--by her geographical size, by her population size-by her history and heritage and the civilization that India carries, has to play a role not only in the Asia-African region but in the globe itself. And we have to balance China too. We have to control important events that may take place in the Indian Ocean region. We must control the Indian Ocean region substantially. We must gain acess to control Asia compulsion to meet threats and grow on a nation. These are our vital, if we have to survive, if we have to prosper as a nation. What is more, we find in vital matters of India, constant and continuous interference are there from certain super powers. India must be able to contain this phenomenon and say that we will not tolerate such interference in our affairs. This has to be considered. I believe, as a free Indian, It is my birth right to live a free life. We are not so small a nation that we should be brow-beaten. I have a tremendous civilization and heritage. The blood that flows in me is a blood that contains a lot of vibration. Therefore, I think when you consider our security threat, we have to assess it fully. I am sure some of our policy-makers have done it.

According to that India has to have a status in the international community. It must have a status natural to its strength, history and heritage. If India does not have a status, then Britain will have a status, France will have a status because they were once glorious nations. Great Britain was once ruling over the world where the sun did not set. They can remain a nuclear power and all that. Today, the emerging India, the democratic India, with such a big size, population and resources is going ahead. But it cannot have a place in the Security Council. India cannot go in for any nuclear experiment. If this is the scenario, then I say—I may be differing from my party's view—that keeping all these things in mind our scientists, our policy-makers,what they have done, they have done correctly so far. What I demand from the present Government is that the programme should be on. It should not be delayed. Let it be our missiles development programme which Indira Ji started in 1982 with a vision and our scientists have achieved wonders. You have given the Bharat Ratna Award to Dr. Abdul Kalam recently which is a very befitting thing. Our scientists have done wonders. They have made breakthrough. No power in the world can out-match us in this field. But we can match any body and this is being stalled today because of certain considerations. We don't like to see that, and therefore, I say that our nuclear programmes for peaceful purposes is fine. But the programmes should be on and not interfered with. Some parts of programmes have been carried out. Whatever is necessary, should be carried out. It should not be stopped at the dictation of any body. We need not make a ceremonial declaration that we are going to be a nuclear weapon state. It is not necessary. We have not signed the CTBT. We have not signed the NPT. We are not going to place the world at the hands of some colonialist who wants to make the rest of the world a colony of a Nuclear club and who will rule over the globe for ever. India cannot accept such a position, and therefore, India has got a role to play. I would like to recall the vision and statemanship of the great Chinese leader—Mao Tu Jung. He told the people way back in 1958 that if China was not to be bullied, then it had to go in for nuclear weapons. That was the view expressed by him and he did it. In 1964, China conducted the first nuclear test and went ahead.

We pleaded for the People's Republic of China for its entery into the United Nations. Pt. Jawaharlal Nehru pleaded so

much for them. He championed their cause. America would not even admit. They would treat Taiwan as China. But Mau changed things. This is the way of doing things. In 1971, China entered the United Nations and became the Member of the Security Council. Today, China is one of the five members of the Security Council and America gives them a tremendous respect. Without power projection, there is no foreign policy. Without power projection, there is no defence policy, and if an independent nation like India, does not project itself as a power, it has no economic future. It cannot give a fair deal to its people. So, I think we should have a serious thinking on this matter. The new government has said that they keep their nuclear options open. What do they mean by keeping the nuclear option open? I have not understood it. I was not a very bad student. But I have not understood as to what they mean by 'keeping our nuclear option open.' Does it mean that in five minutes, the country can go nuclear? What we need to have today is that we must have a command. We must have an operational command and communication system. Do that and go ahead. So, I for one, say that the present Government, at least, should not fight shy of conducting what is going on in this field. No new programme needs to be taken up. Many people frighten us by referring to the financial aspect. They say that the financial burden is too much. This is not at all so. Even to create a limited deterrent which we need very badly, the financial aspect is involved. There is nothing new in it.

The financial aspect is nothing. We have already incurred a lot of expenditure for doing what we should have done earlier. So, there was no transparency in discussing these matters in threadbare details. You get all this information from a floppy which can be purchased in the American *bazar*. The rest of the world knows where we are only we do not know where we are and what we are what we could be.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Dr. Dutta, please conclude.

DR. B.B. DUTTA: Sir, I am making some very important points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): That we know. Please conclude now.

DR. B.B. DUTTA: Yes, I am concluding. I am concluding.

My third point is this. You have mentioned about Swadeshi and you have mentioned about a commission for constitutional review. You have also mentioned that parliamentary arithmetic alone could not ensure a good governance. It requires a consensus. These three things point to one direction. You see what has happened this time. *...(interruption)...* Sir, this is my last point. What has happened this time? When you have parliamentary arithmetic in favour of a ruling party, you have a majority, a two-thirds majority, you can talk about consensus, broadening your base. Fine! it is a very healthy democracy. But what has happened this time? Parliamentary arithmetic has taken away the key. The key has been taken away and we are afraid of instability and an uncertain future. A broader base has to be created. But how has it to be created? Arithmetic is not permitting it. It is creating problems for ensuring only good and effective governance. Now I ask a question whether is it the system, that is at fault? I had put this question to myself, to my colleagues and to everybody whether it is the system that is failing or whether we are failing the system i.e. whether those who are actors in the system are failing. Many people say that the actors are failing, the system is sound. But as far as I understand the social science I can say this, if the system is sound, it should automatically bring into play the inherent corrective mechanism that should be there. But this is not happening. Why are parties multiplying? Instead of the number of

parties becoming less and less over the decades they are on the increases. In the last elections we had less than 30 parties; now we have got more than 40 parties—the parties are multiplying and the spectre of instability is haunting the country. Therefore, I, for one, do believe that this system is not showing signs of going ahead. It requires a systemic correction. We cannot but ask the question whether the Cabinet type of Government is going to hold good for long. Sir, many people, including statesmen and former Prime Ministers have said—even Atal Behari Vajpayee ji when he was not a Prime Minister, spoke in a seminar after he lost his Prime Ministership last time—"We want a Presidential form of Government." Chidambaramji has said so, Vasant Satheji has said so. Now when these results have come, nobody talks about it. I say, "Let us start a discussion. Your constitutional review should point out where we are failing." Sir, in another direction also, we are failing. In the Constitutional review I want you to take note of it that we in India feel suffocated today with colonial institutions and colonial type of administrative framework. What the British left, we have expanded them, stretched them to the limit. They are not working. We must evolve our adminstrative system right from the village; read, re-read and re-read Gandhiji, go in for decentralisation, make India more of a federal structure. We must also see that the top Executive in the States and in the Centre is directly elected and that there is stability and good and effective governance. I think it is high time that we reflected on our Indian ethos, our social ethos, our political ethos and visualised what type of administration and what type of polity we should have. We should very seriously think it over. So, I welcome the very idea of a Constitutional review. Though it is a very minimal promise, I think we should start talking about it because if this Government falls....*(interruptions)*...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please conclude.

DR. B.B. DUTTA: Yes, Sir. Nobody can guarantee that this Government will not fall. Then what will happen? Another election; then more political parties, then another election, and thousands of crores of rupees going down the drain and economically we are going to become bankrupt. And then they will be telling us, "Our economy doesn't permit us to do this and to do that because we are a poor country!"

I refuse to believe that we are a poor country . We are a very, very rich country. Poor people manage this great country in the poorest manner and that is why we are poor today. We can do wonders in human resource development.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please conclude.

DR. B.B. DUTTA: Yes, Sir. We are a very rich nation. Please behave in a rich way. Thank you.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, now very few Members are present here. Therefore, I propose to drop most of the points which I was going to raise.

The first point about which I would like to talk is the so-called national agenda. Several days had been taken for preparing the agenda. There were election adjustments. The election was not based on any agenda. There were seat adjustments and then on the question of the National agenda some discussion took place for some time and ultimately in the name of a national agenda some programme is made out. I submit that it is not a national agenda. it is a prantic agenda. All the State and regional parties which have joined the alliance to form a Government forced upon them their points, their packages, for inclusion in the agenda. They they were all included in the agenda named as the national agenda. As you know, there is something called modern art. Some pictures are made. But, in fact nobody can find any picture there. There is no picture. But it is called modern art. Now this national agenda is also a modern art.

A number of suggestions are made by the regional parties and then they are termed as the national agenda. Atalji has said something somewhere in Rajasthan. It appeared in the Press in Gujarat. He was ridiculing the United Front people.

कहीं की ईट कहीं का रोड़ा।
भानुमति ने कुनबा जोड़ा।।

सर अब यह क्या है? अटल जी ने कुनबा जोड़ा।

All these parties have suggested some programmes and everything is accepted As my DMK friend has pointed out, even a two-Member party has been given one ministerial post and even if there is only a single Member, he has been made a Minister to constitute a particular figure. That is the way in which the Government has been formed. I don't want to go into the allegations relating to Sukh Ram and others. Everybody knows what had happened here when the issue relating to fodder scam involving Lalu Prasad Yadav was raised. The House could not work for some days. At that time the whole orchestra team of Sikander Bakht Sahib went to the well and they did not allow the House to work. When a question was asked to Atalji on a TV interview taken by Pritish Nandi and Javed Akhtar as to what he had to say about the charges against Jayalalita, Atalji said, "They are only chargesheets. This is not a conviction". I like Atalji. I respect him very much. I know he is a very nice man. Just like Dharmaraja's rath touched the ground when he said narova kunjrova, Atalji's rath also touched the ground when he said, "These are only chargesheets". Who is convicted? Nobody is convicted. In the name of chargesheets a lot of demonstration took place in this House. But nobody has been convicted. But Atalji said this because he has got the compulsion of forming a Government and all that. I would like to say one thing here. The BJP has broken all the parties. Everything must have been done with his consent. What had happened in Uttar Pradesh? All the parties had been broken. The Congress had been broken. The BSP had been broken. The Janata Dal had been broken. They are accusing Shankarsinh Waghela. Why do they accuse Shankarsinh Waghela? They can break all the parties in Uttar Pradesh and form a Government of 95 Ministers. And they are blaming Shankarsinh Waghela when it is their own culture! Shankarsinh Waghela belongs to their party. Forty per cent of the BJP members in Gujarat were from different parties and they ruled the State. And they blame Shankarsinh Waghela! When they did something in Uttar Pradesh it was okay; it was good; it was in the interest of the nation. My suggestion is that 95 तो है पूरे 100 कर लीजिए, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के इतिहास में आपको गोल्ड मैडल मिलेगा, कर लीजिए वहां। If somebody is doing something wrong, then you shout. But if you do something, then it is okay!

Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not want to take much time because very few Members are present. I want to say that two things are required to be considered very seriously by the Government. I request the Leader of the House that one is child labour in this country. I know the compulsions of poor people. They send their children to small hotels and factories. Young children are working even in hazardous factories in this country. But the problem of child labour is very serious. There is no question of any party here. There is a reference to child labour in the BJP manifesto. That is why I am saying this. Sir, there should be some programme to eliminate child labour as much as possible. Total elimination of child labour in this country, I think, is practically impossible. But whatever can be done must be done.

Secondly, the most important thing, which, I believe, is a shame on this country, shame on everybody, is scavenging. Scavenging is prevalent in all the States of India, except perhaps Kerala. This is still going on in some parts of Gujarat. We have the same inhuman system even after fifty years of independence when we are talking about Mahatma Gandhi, independence and everything. Scavenging system should be

eliminated. By law it should be eliminated. Whatever financial assistance is required to be given to different States for eliminating this system, it should be very seriously considered by this Government. I know Shri Atalji who is at the helm of affairs. He is very much concerned about this inhuman system, which is a shame on all of us. I request that a serious view should be taken to eliminate child labour and scavenging.

Thank you.

श्री मोहम्मद आज़म खानः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि शायद इतिहास के सबसे छोटे सदन में, जहां सबसे कम सदस्य हों, आपको उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का और मुझे बोलने का मौका मिला है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक रस्म है महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा की और उस रस्म की अदायगी मैं भी कर रहा हूं। ऐसे वक्त पर जब हमारा देश 50 साल की आजादी को पूरा करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे वक्त में हम सबकी, यहां सदन में बैठने वालों की और मुल्क में रहने वाले तकरीबन् 100 करोड़ इंसानों की जिम्मेदारियां थीं, उन्हीं जिम्मेदारियों में और उन चैलेंजिस में राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हमारे सामने आया और उस पर यहां चर्चा हो रही है। एक सरकार ऐसी इस वक्त देश में है, जिसके मुखिया ने और जिसके जिम्मेदारों ने कुछ रोज़ पहले, जैसा हमारे एक साथी ने कहा "कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा", लेकिन यह महाकुनबा जोड़कर आज सत्ता में हैं और बड़े गैरऊसूली तौर पर है। जिस मेनिफेस्टो पर इलेक्शन जीतकर आए हैं, उस मेनिफेस्टो पर सत्ता में नहीं हैं और, महोदय, आज नहीं तो कल, दो साल बाद, पांच साल बाद, दस साल बाद, 20 साल बाद इसी देश में वह दिन भी आएगा जब लोग बिल्कुल खारिज कर देंगे ऐसे लोगों को, जो यह कहते हों—यह तोड़ देंगे, इसे निकाल देंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, इसे मार देंगे, इस बस्ती को जला देंगे। लोग ऐसे लोगों की तलाश करेंगे कि ऐसे देश तोड़ने वाले* देश के दुश्मन कहां रहते हैं? क्योंकि जरूरत आज इसके अलावा भी बहुत सी चीजों की है। यह समझा जाता था, जब इलेक्शन का मेनिफेस्टो लगभग सभी पार्टियों का शाया हुआ, जी चाहता था हमारी आंखें कहीं यह देखें क्योंकि डिस्कशन हुआ हाउस में.....

*Expunged as ordered by the chair.

हमारे इंटलैक्चुअल साथियों ने न्युक्लिअर पौलिसी पर फारेन पोलिसी पर तथा बहुत सी चीजों पर बहुत अच्छा बोला। हमारी सरकार के एक मंत्री ने दिल खोलकर रख दिया। हमसे बाद आजाद होने वाला चीन हमारी सरहदों पर बसा हुआ देश जिससे अमेरिका घबराता है उसके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम कि उसकी ताकत क्या है। उसने दुनियां से नहीं कहा कि हम कौन सी चीज बनाने वाले है और हमने क्या हथियार बना लिए है। लेकिन जब हमारी बगल में कोई खुशबू लगी होगी तो दिखेगी तो नहीं लेकिन उसकी सुगंध पूरा माहौल महसूस करेगा। हमारे गिरेबान में गंदगी हो, मुमकिन है कि हमें उसकी बदबू न आए लेकिन हमारे दाएं, बाएं और आगे-पीछे बैठने वाले पड़ोसी को उसकी बदबू आएगी। अक्सर महसूस किया होगा आपने गरमी के जमाने में अपने पैर से जूते निकाल लीजिए, बदबू अपने-आपको नहीं आती लेकिन डिब्बे में बैठे हुए लोग अपनी नाक पर रूमाल लगा लेते हैं। हमारा जी चाहता था यह देखकर कि गरीबी का इलाज, भुखमरी का इलाज, जिलालत का इलाज कहीं मेनिफेनटो में ऐसा नहीं हुआ, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कितनी आबादी आज भूखी है, कितने लोगों के पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। अभी चाइल्ड लेबर की बात की है हमारे साथी ने। 1992 में मैं उत्तर प्रदेश में लेबर मिनिस्टर था। खुर्जा की कुछ फैक्ट्री पर मैंने छापा मारा। उनमें 4-4, 5-5 और 6-6 साल के छोटे बच्चे बर्तन बना रहे थे। मैंने पुलिस बुलाई और उनके उन बच्चों को हवाले किया, काम कराने वाले लोगों को हवाले किया। उसके बाद गाड़ी में बैठा और देहली चला आया। यू०पी० निवास में मैं ठहरा था, मेरे पास खुर्जा के कुछ जिम्मेदार लोग आए और उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को वापिस ले लें। मैंने कहा-नहीं, यह बहुत गैर इंसानी बात है कि 4 साल, 6 साल के बच्चों से काम लिया जाए। थोड़ी ही देर बाद उन बच्चों की मांएं आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा शौहर नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे परिवार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है सिवाए इसके कि मैं कोठे पर बैठकर पेशा कराऊं। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मैं मजबूर था मुकदमा वापिस लेने के लिए और मैंने ऐसा ही किया। एक ऐसे हिन्दुस्तान में जहां आज भी हमारी हजारों बहनें, हमारी लाखों मांएं सड़क के किनारे बैठकर टट्टी करती हों और हमारा 50 साल का आजाद हिन्दुस्तान मोटरों की रोशनी से उनकी इज्जत को बचा न सका हो और वह खड़ी हो जाती हों और फिर हम कहें कि हमें गर्व है और फिर हम यह

नारा लगाएं कि —"बच्चा-बच्चा राम का, कुरबानी के काम का।" तो फिर दिलों पर हाथ रखकर तय करना होगा और सोचना कि देश की तरक्की होगी या नहीं होगी? यह देश किसानों का है।

"If you want to see India, go to the villages. You will see India there."

क्यों कहा था गांधी जी ने? इसलिए कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई उसी नंगे ने लड़ी थी, उसी भूखे ने लड़ी थी जो गांवों में रहता है, जो खेत में हल चलाता है जिसका पसीना खून बनकर जमीन पर गिरता है और फिर पूरा हिन्दुस्तान उससे अपना पेट भरता है। वह किसान तो आज भी नंगा है। उस किसान को गन्ने का दाम नहीं मिलता, उस किसान को गेहूं का दाम नहीं मिलता, उसका आलू खेत में दोबारा ही बो दिया जाता है और उसकी खाद बन जाती है। ऐसे देश के लिए अभिभाषण में यह होना चाहिए था कि देश के किसानों के लिए पौलिसी क्या हो। यह तो कुछ भी नहीं था। लाखों हेक्टेयर जमीन हिन्दुस्तान में बंजर पड़ी है, ऊसर पड़ी है। कोई प्लान नहीं है किसी सरकार के पास और वह जो देश को बदलने का दावा करते हैं, जो अभिभाषण हाथ में पकड़ा दिया राष्ट्रपति महोदय के पढ़ने के लिए— इस लाखों हेक्टेयर जमीन पर काम होगा या नहीं होगा, यह जमीन उपजाऊ होगी या नहीं होगी, इसके बारे में नहीं सोचा गया। बेरोजगार हाथों के बारे में नहीं सोचा गया, हमारे बेशुम्मार नौजवान डिग्रियां हाथों में लिए हुए सड़कों पर घुमते हैं, टेरोरिस्ट बन जाते हैं। उनके कल के बारे में नहीं सेचा गया। क्यों नहीं सोचा गया, यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हरएक व्यक्ति को चिन्तन करना होगा, हरएक व्यक्ति को सोचना होगा और यही कहने के लिए मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं और दुखी हूं इस बात से कि इन सारे चेलेंजेज का मुकाबला करने के बजाय, इन सवालों को उठाने के बजाय ऐसे सवाल देश के सामने उठाए गए जिनसे देश कमजोर हुआ देश मजबूत नहीं हुआ। देश कमजोर किन सवालों से हुआ? कमजोर हुआ इस सवाल से कि धारा 370 बदलेंगे, कमजोर हुआ इस सवाल से कि हम मस्जिद गिराकर मंदिर बनाएंगे। देश कमजोर हुआ इस सवाल से कि यूनिफार्म सिविल कोड लागू करेंगे। धारा 370 तो आप बदलेंगे लेकिन इसी संविधान में धारा 371 भी है, उसके बारे में कोई विचार आज तक नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि धारा 370 का रिश्ता हिन्दुस्तान में रहने वाली उस अखलियत से है जिसे मुसलमान कहते हैं और जिसके लिए यही नारा लगा कि "तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान।" यूनिफार्म सिविल कोड इसलिए बहस में नहीं आया कि देश में रहने वाले सभी धर्मों से एक जिस्ट निकालकर कोई कोड बनाया जाए बल्कि इसलिए कि कब्रिस्तानों पर कब्जा किया जाए, इसलिए कि मुसलमानों के अकीदे से खिलवाड़ किया जाए, इसलिए कि मुसलमानों को छेड़ा जाए, इसलिए कि हिन्दुओं के जज्बातों से खेलकर एक खास नाम पर नफरत फैलाकर सत्ता हासिल की जाए। भारतीय जनता पार्टी के ऐजेंडों से अलग नेशनल एजेंडा जारी हुआ और उस नेशनल ऐजेंडा में यह कहा गया कि इन तीन जज्बाती सवालों पर कोई बहस नहीं होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हमारे प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने उस सदन में वायदा किया और कल इस सदन से भी वायदा करेंगे, देश में रहने वाले करोड़ों लोगों से उन्होंने वायदा किया, भानुमति के महाकुनबे से वायदा किया कि हम इन तीनों सवालों पर कोई बहस नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। जब प्रधान मंत्री लखनऊ तशरीफ ले गये तो प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि हम डिस्कशन से इसे तय करेंगे। बातचीत से तय करेंगे। अगर यह मुद्दा बातचीत से तय होने का था तो बातचीत से तय करने के लिए तो बहुत पहले हमारी सरकार में भी कहा गया था। मुलायम सिंह सरकार में यही प्रपोज़ल था कि या तो बातचीत से यह मुद्दा तय होना चाहिए वरना अदालत का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या यह देश कानून का रहेगा क्या संविधान का यह देश रहेगा जहां हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उसके मुख्य मंत्री एक मुजरिम को हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत - जिसके बाद कोई अपील नहीं है सिवाय आसमान के - उस अदालत ने उसे एक दिन की सजा की हो और उसका जुर्म क्या हो? जुर्म यह है कि उसने 6 अक्तूबर 1992 को पूरे देश में फसाद पैदा किया था। उसने इंसानों की जानों से खिलवाड़ किया था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गयी थी। इस इल्जाम में जिस व्यक्ति को एक दिन की सजा हुई हो, वह हिन्दुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्य मंत्री है।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Mr. Vice-Chairman, I feel that these allegations are incorrect. The factual position is that the case against him was for the contempt of the court because he could not keep the promise which he had made earlier to the court.

This kind of an allegation - rape, etc., is objectionable.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आजम जी, सुनिए ...**व्यवधान**.. किसी चीफ मिनिस्टर

मोहम्मद आज़म खान: उपसभाध्यक्ष महोदय ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप एक मिनट बैठिए, मैं बताता हूं । ..**(व्यवधान)**..

मोहम्मद आजम खान: महोदय, यही एक सवाल ऐसा है, जिस सवाल पर देश जुड़ेगा या जिस सवाल पर देश बहुत भयानक इम्तिहान से गुजरेगा। यह ऐसा सवाल नहीं है, जिसको एक व्यक्ति के कह देने से ...**(व्यवधान)**...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, आजम जी के भाषण में *शब्द का इस्तेमाल किया गया है फिर भी हमने ऐतराज नहीं किया। यह अनपार्लिया-मेंटरी है। और भी बहुत से शब्द इस्तेमाल किये गये हैं लेकिन ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि):* जो है, देट विल बी ऐक्सपंज्ड फ्रांम दी रिकार्ड ..**(व्यवधान)**.. *जो अनपार्लियामेंटरी है, वह सब ऐक्सपंज हो जाएगा। ..**(व्यवधान)**..

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: महोदय, धैर्य की भी एक सीमा होती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): महोदय बस, अब मैंने कह दिया है । आप बैठ जाइए। आई हैव आलरेडी स्टेटिड। आज़म जी, अब आप समाप्त करिए।

मोहम्मद आज़म खान: महोदय, अगर अपनी बात जो मैं नियमों के अंदर कह रहा हूं जो बात मैं संसदीय भाषा में कह रहा हूं, जो बात मैं फैक्ट्स पर, सच्चाई पर बेस्ड कह रहा हूं कि एक ऐसी सरकार जिसने राष्ट्रीय एकता परिषद में यह वायदा किया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदशों का उल्लंघन नहीं करेगी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगी, यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया हो, इसके बाद उस हलफनामे के खिलाफ बाबरी मस्जिद को तोड़ती हो अगर यह कहना असंवैधानिक है, अगर यह कहना गलत है तो मैं आपसे नहीं पूरे देश से माफी चाहता हूं। अगर यह कहना गलत नहीं है तो हमें यह कहने की इजाजत दी जाए। दूसरे बहुत से सवाल थे जिन पर देश में बहस होनी चाहिए थी। उन सवालों पर बहस नहीं हुई। इन जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और इन जज्बाती मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आज़म जी आपका दस मिनट का समय हो गया है।

मोहम्मद आज़म खान: मेरी पार्टी के दो सदस्यों का भी समय है।...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नहीं-नहीं, आप अपनी पार्टी के समय से ज्यादा समय बोल चुके हैं। ...**(व्यवधान)**...

मोहम्मद आज़म खान: क्योंकि दूसरे साथी यहां पर नहीं हैं, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसी): नहीं-नहीं, आप यहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम आपको बोलने के लिए अलाऊ कर रहे हैं।

मोहम्मद आज़म खान: मान्यवार, मैं जरूर आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और आपने मुझे खूब बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसी): आप कनक्लूड कीजिए।

मोहम्मद आज़म खान: मैं बिल्कुल कनक्लूड कर रहा हूं। अन-आर्गनाइज्ड मजदूरों की बात यहां सदन में चली। अन-आर्गनाइज्ड मजदूरों में हमारे बहुत से मजदूर आते हैं जैसे—होटल में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, झल्ली उठाने वाले, ठेला खींचने वाले, खेत में काम करने वाले, ये सब हमारे मजदूर हैं। यह बड़ी दुखद बात है कि इस सरकार ने उन श्रमिकों के बारे में, उन मजदूरों के बारे में जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बारे में सिर्फ डेढ़ लाइन में ही अपना मकसद पूरा कर दिया है। अन-आर्गनाइज्ड मजदूरों के लिए कोई कमीशन बैठाया जाना चाहिए था, उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए था, वह नहीं हो सका है। मैं सरकार से चाहूंगा कि अन आर्गनाइज्ड किसानों के लिए और दूसरे मजदूरों के लिए एक कमीशन बैठाया जाना चाहिए और उनके भविष्य के बारे में सोचा जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और आखिरी कहूंगा कि कांस्टीट्यूशन को रिव्यू करने की बात आई है। इस देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, इससे उनके दिलों में एक सुबहा और डर पैदा हुआ है। कल हमारी एक बहन ने यहां अच्छा भाषण किया।

*Expunged as ordered by the Chair

इस मुल्क में रहनी वाली अक्लियतों पर उन्हें हमदर्दी थी। मेरी बाहर भी उनसे बात हुई। उन्होंने हमारी बस्तियों में, हमारे घरों पर टंगे हुए फटे हुए परदों की बात की, हमारी बहनों और बेटियों के चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों की बात की, उनकी आंख के नीचे की काली स्याही की बात की। उन्हें बड़ी हमदर्दी है और मुझे उनकी हमदर्दी पर हमदर्दी है। लेकिन मैं उसी वर्ग का एक कमजोर व्यक्ति आपके सामने खड़े होकर यह कहना चाहता हूं कि मैं उन फटे हुए पर्दों के लिए आपसे हमदर्दी नहीं चाहता हूं, मैं आपसे तरस नहीं चाहता हूं, मैं आपसे रहम की दरख्वास्त और भीख नहीं चाहता हूं, मैं उनके लिए इन्साफ चाहता हूं और इन्साफ ऐसे नहीं मिलेगा। काकोरी काण्ड को लेकर असफ़ाक उल्ला खां फांसी के तख्ते पर चढ़ गये और उन की अक्लियत के किसी भाई के मामूली से छप्पर की होली के दिन होली जला दी जाए, और जब दो भाई अपनी गुरूबत की बिनाह पर शादी तक न कर सके हों, अपनी बूढ़ी मां और बहन को पाल रहे हों और वे दो भाई जब अपना छप्पर मांगने के लिए जाएं तो पत्थर से उनका सिर कुचल कर भेजा बाहर निकाल दिया जाए और छुरे से काट कर उनके सिर, उनके धड़ों से अलग कर दिए गए। यह हुआ है इसी होली में। क्या यही है कानून का राज? यही है उत्तर प्रदेश की सरकार? जहां एक ऐसा मंत्री था जिसने केबिनेट मिनिस्टर होने की ओथ ली हो और जिस दिन उसने ओथ ली उस दिन उसका नॉन बेलेवल वारंट जारी था। नॉन बेलवल वारंट होने के बावजूद उसने केबिनेट रैंक के मिनिस्टर की ओथ ली। हमें यह देखते हुए और सोचते हुए शर्म आती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि हीनियस क्राइम का वह मुजरिम था, उसको केवल जमानत नहीं दी बल्कि उसके अरेस्ट पर स्टे दे दिया गया कि हां यह गिरफ्तार नहीं किए जायेंगे। ऐसे लोग जब संविधान को बदलने की बात कहें और संविधान को रिव्यू करने की बात करें... (**व्यवधान**)...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने की किसी प्रकार की आलोचना ...(**व्यवधान**)...

मोहम्मद आज़म खान: नहीं-नहीं मान्यवर, यह आलोचना नहीं है। यह सूचना है ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): नहीं-नहीं, यह सबजेक्ट नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं समझ गया, मैं समझ गया ...(**व्यवधान**)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir he is speaking on the subject only. ...(*Interruptions*)...Sir, this is the subject matter ...(*Interruptions*)...He is not interfering into the court matter...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The matter is *subjudice*...(*Interruptions*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: There are all facts. If such a persons thinking of a revival of the Constitution ...(*Interruptions*)...What he is thinking of? ...(*Interruptions*)...That is the question...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please, listen to him...(*Interruptions*)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: It is the Parliament and the people of the country who will decide...(*Interruptions*)...If any body has any grievance against the judgement of the High Court, they can go the Supreme Court.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: That is what I am also saying. But, you cannot dictate in the middle ...(*Interruptions*)...He should be allowed to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hanumanthappaji, please, sit down..(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैं बोल रहा हूं। आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए मैं बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं कंट्रोल कर रहा हूं। आई एम कंट्रोलिंग इट ...(**व्यवधान**)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Is it time to review the practice of the hon. High Court? No, it is not fair ...(*Interruptions*)...It is not fair (*Interruptions*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: No, no, you cannot ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): एक मिनिट रुकिये। मैं कहता हूं कि आप बैठ जाइये ...(**व्यवधान**)...।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I am listening to the Vice-Chairman, Mr. Hanumanthappa ...(*Interruptions*)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): हनुमनतप्पा जी, आप क्यों उठ रहे हैं? आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये, मैं आपको कह रहा हूं।...(**व्यवधान**)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: But, Sir ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): That I know ...(*Interruptions*)...

That I know...(**Interruptions**)...

मोहम्मद आज़म खान: उपसभाध्यक्ष महोदय, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): सुनिये, आपके दो-तीन एजेंडा हैं। यू आर स्पीकिंग वैरी वैल। आप डिस्प्यूट में क्यों जा रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

मोहम्मद आजम खान: मान्यवर, मैं डिस्प्यूट में नहीं जा रहा हूं बल्कि मुझे तो इस बात का खेद है। ...(**व्यवधान**)...

श्री हनुमनतप्पा: यह उनका सब्जेक्ट है। इस पर उनको बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ...(**व्यवधान**

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: इसी को कहते हैं कि आग लगाने के लिए ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): सुनिए सुनिए। आग लगाने की बात नहीं है। ...(**व्यवधान**) Let us have a good discussion. You are talking of some agenda. Please, please ...(*Interruptions*)... Please, please ...(*Interruptions*) Your agenda in certain things is very, very classical...(*Interruptions*)...

मोहम्मद आजम खान: उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात का है ...(व्यवधान)... आप अपने विवेक से बोलिए...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपको खेद है तो यह खेद हो चुका है।

मोहम्मद आजम खान: मैं चाहूंगा कि आप अपने विवेक से बोलें और आप इधर उधर के विवेक से न बोलें।...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): No, no, do not talk like that...(*Interruptions*)

मोहम्मद आज़म खान: आप इस कुर्सी की महिमा को बरकरार रखें और अपने विवेक से निर्णय लें, इधर उधर से न लें।...(व्यवधान) इस कुर्सी की महानता को पहचानते हुए महान बनिए...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): सुनिये,

मोहम्मद आजम खान: मान्वयर, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है वह कोई छुपी हुई बात नहीं है। अदालत में एक फैसला हुआ। मैंने कहा कि मैं यहां उस फैसले पर बहस नहीं कर रहा हूं, डी-मेरिट पर नहीं जा रहा हूं। मैंने केवल एक सच्चाई बताई है, एक वाकया बताया है और आए दिन सदन में यह होता है। हम यहां अदालत के फैसले पर बहस नहीं कर सकते।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): प्लीज कनकलूड कीजिए, आपका समय हो गया है। योर टाइम इज ओवर।

मोहम्मद आजम खान: मान्यवर, मैं इसी पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मान्वयर, हम जैसे कमजोर लोगों को इसी बात का डर है कि जो लोग फासिस्ट हैं, जो लोग धोखा देने वाले हैं समाज को और देश को, जिस मैनिफैस्टो पर चुनाव लड़कर आते हैं उस मैनिफैस्टो को ताक पर रखकर नेशनल एजेन्डा बनाते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): यह सब रिपीट हो रहा है।

मोहम्मद आजम खान: उन लोगों से हमें डर है कि जब ये कांस्टीट्यूशन का रिव्यू करेंगे तो ये रिव्यू नहीं करेंगे। कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं और बहुत से अमेंडमेंट्स हुए भी हैं इन 50 वर्षों में, आइन्दा भी हो सकते हैं। लेकन ये अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो कांस्टीट्यूशन को रिव्यू करने की बात करते हैं। इनकी नजर फंडामेंटल राइट्स पर है, इनकी नजर उन चीजों पर है जो स्प्रिट आफ दि कांस्टीट्यूशन हैं। ये पढ़े-लिखे लोग हैं। ये जानते हैं कि अदालत में जाकर ये इसे नहीं बदलवा सकते। इनको मालूम है कि फासिस्ट जाहिल नहीं होता, फासिस्ट पढ़ा-लिखा होता है। फासिज्म यूं ही नहीं आया, फासिज्म भी इसी तरह जम्हूरियत के रास्ते से दाखिल हुआ। हिटलर पहले पार्लियामेंट में आया। वहां पर उसने अपनी असरियत बनाई।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): प्लीज कनकलूड कीजिए।

मोहम्मद आजम खान: उसके बाद हिटलर हिटलर बना। मान्यवर हमारा यह खतरा और अंदेशा है कि जब ये कांस्टीट्यूशन के रिव्यू करने की बात करते हैं, क्योंकि ये पढ़े-लिखे लोग हैं, इन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच का यह फैसला है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज मिलकर इसी फंडामेंटल राइट्स और प्रिएंट आफ दी कांस्टीट्यूशन को नहीं बदल सकते इसलिए हमारा यह दर है कि जो नेशनल एजेंडा पेश किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हम कांस्टीट्यूशन को रिव्यू करेंगे। कांस्टीट्यूशन को रिव्यू नहीं खत्म करें और ये हिन्दू राष्ट्र कायम करेंगे, इस मुल्क से जम्हूरियत का जनाजा निकालेंगे। डैमोक्रेसी और सेक्यूलरिज्म खत्म होगा। ये उसके दरवाजे को खोलना चाहते हैं। इस खतरे को आपके तथा देशवासियों के सामने रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI S. MUTHU MANI (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of the AIADMK, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address.

I am happy that unlike the earlier Governments, this Government has taken care to include the regional aspirations in the Address by the President.

Since ours is a federal polity and because of the fact that only prosperous States can make a strong India, our Leader, Dr. Puratchi Thalaivi, put forth a charter of six demands for the well-being of the Tamils and Tamil Nadu. I find that all these demands have been covered in the Address. I am hopeful, the Government would soon translate these into action. Because of the paucity of time, I would just make a few points and conclude.

The Government has committed itself to making labour an equal partner in national reconstruction. Paragraph 21 of the President's Address makes a mention about it. It is the sweat and toil of the labourers that has made India self-sufficient in many areas. But unfortunately, very little has been done for them.

As a trade unionist, I have been pleading their cause for several years, inside and outside the House. Still many demands of the workers have not been met.

Sir, the workers of over 240 Central public sector undertakings have been demanding pension as a third benefit, in addition to CPF and gratuity. This has not been accepted by the Government. So, I appeal to this Government to bring a legislation in the forthcoming Session, to give the PSU workers pension as a third benefit, without any new condition. In the same way, bonus should be given to all the employees, without any ceiling fixed in respect of salary.

The fear of retrenchment created by the previous Government's policies is still alive in the minds of the workers. Many PSUs. With a potential for growth have been declared sick and non-viable, throwing thousands of workers out of employment. Up to June, 1997, 2692 sick units were referred to the BIFR. Out of this, 406 cases were dismissed as non-maintainable and 496 units were asked to wind up. This trend continues even today. Since this Government has declared that 'India shall be built by Indians', I appeal to the hon. Prime Minister to provide funds for the revival of these sick units so that they can prosper and make their contribution towards nation-building. This step would make thousands of lights glow in the homes of our workers who have made India prosper.

Of the total workforce, only 15 per cent is on regular employment, getting a fixed wage. Nearly 85 per cent of the workforce is unorganised, of which agricultural labourers account for 65 per cent. These agricultural workers are living in misery because of the low wages and the unseasonal nature of their job. They have no organisation to take up their cause. The same is the case with the building and construction workers. Legislations were enacted to protect their interests. But nothing worthwhile has been done for them. I make a fervent

plea to the Government to do something, on a war-footing, for the agricultural workers, the building and construction labourers and other unorganised workers, and save them from their misery.

Sir, I have a word on language. Our Leader has demanded that Tamil should also be made an Official Language. It is our right to plead such a status for our language. This Government has committed itself to declaring all the languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution as Official Languages of the Union. We are happy about it. When we ask for a right place for Tamil, our mother-tongue, we are misunderstood and are accused of being against Hindi. This is not correct. Let me make this point clear. We are only against the imposition of Hindi on us. We will oppose the imposition of any language on us. The way you love Hindi, let us love our mother-tongue, Tamil. Let me say one thing more. We are not enamoured of English. Since English has come to stay in this country, let it remain as a link language, as an associate language. This is all we say about language.

It is a fact that those coming from the non-Hindi speaking states have a strange feeling in Parliament. We find that those hon-Members whose mother-tongue is Hindi are free to speak in Hindi at any time they feel like. But those unfortunate ones who do not know Hindi have to give advance notice to the Chair to speak in their mother-tongue. Sir, the Constitution does not prohibit a person who does not know Hindi or English from contesting in the elections. A person who knows only Tamil or Telugu or Malayalam or Kannada or Bengali or any other Indian language is free to contest in the elections and enter Parliament. Then, is it not a violation of the Constitution to muffle his voice by imposing conditions when he wants to speak in his mother-tongue in Parliament?

During my tenure of six years here, I had brought this handicap to the notice of the hon. Chairman several times. But nothing has been done so far. I wish to ask: why not appoint more Interpreters in all the Indian languages and give freedom to Members to speak, and listen to, in their mother-tongue?

A Member who does not know Hindi and English, cannot understand the procedure of the House because speeches are not interpreted in other Indian languages. Sir, I hope this Government, Atal Behari Vajpayee Government will render justice to all the hon. Members of Parliament.

When I say this, Sir, I am also reminded of one thing. Interpretation is a highly skilled job. Those who are capable of doing interpretation must be paid well and looked after well. I learn that in matters of promotion and provision of other amenities, they are left far behind. If it is so, it should be corrected so that they are not discouraged. I am sure the Secretariat will take care of this and will do the needful.

With these words, I conclude.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hon. Members, I have to inform that the discussion on the Motion of Thanks is over and that the Prime Minister will reply tomorrow.

The House stands adjourned till 11.00 a.m. on Thursday, the 2nd of April, 1998.

The House then adjourned at one minute past eleven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 2nd April, 1998.